अध्याय 16

भाग-क
आयात प्रतिस्थापन से सामरिक लचीलेपन और सामरिक अपरिहार्यता तक

भारत 2020 के दशक के दूसरे चरण में अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक सुदृढ़ व्यापक आर्थिक (मैक्रोइकोनॉमिक) आधारों के साथ प्रवेश कर रहा है। आर्थिक वृद्धि लचीली बनी रही है, वित्तीय स्थिरता को बनाए रखा गया है, और बार-बार आने वाले वैश्विक झटकों के बावजूद नीतिगत स्वायत्तता संरक्षित रही है। ये उपलब्धियाँ महत्वपूर्ण हैं। साथ ही, भारत की विकासात्मक चुनौती का स्वरूप अब बदल रहा है। भू-राजनीतिक विखंडन, सामरिक व्यापार, अस्थिर पूँजी प्रवाह और तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी की वजह से दुनिया में, अब मुख्य बाधा केवल व्यापक आर्थिक प्रबंधन तक सीमित नहीं रह गई है। वास्तविक चुनौती राज्य क्षमता की गहराई और गुणवत्ता से जुड़ी हुई है।

यह अध्याय दो भागों में संरचित है। भाग–I भारत की विकास संभावनाओं को बदलते हुए वैश्विक परिवेश के संदर्भ में स्थापित करता है और यह तर्क देता है कि भविष्य की आर्थिक शक्ति केवल इस बात से निर्धारित नहीं होगी कि भारत कितनी तेजी से बढ़ता है, बल्कि इस बात से भी होगी कि क्या यह वृद्धि टिकाऊ और उत्पादक क्षमताओं का निर्माण करती है, बाह्य संवेदनशीलताओं को कम करती है, तथा भारत को वैश्विक आर्थिक प्रणालियों में और अधिक गहराई से जोड़ती है। अध्याय इस परिवर्तन को सामरिक लचीलेपन–अर्थात् झटकों को सहने और स्थिरता बनाए रखने की क्षमता–से सामरिक अपरिहार्यता–अर्थात् दूसरों के लिए विश्वसनीयता, क्षमता और मूल्य का स्रोत बनने की योग्यता–की ओर एक संक्रमण के रूप में प्रस्तुत करता है। विनिर्माण, निर्यात, अनुशासित स्वदेशीकरण और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में भागीदारी को न केवल आर्थिक लक्ष्यों के रूप में देखा जाता है, बल्कि ऐसे संस्थागत तनाव-परीक्षणों के रूप में भी देखा जाता है, जो यह प्रकट करते हैं कि क्या राज्य बड़े पैमाने पर सीखने, समन्वय और प्रभावी क्रियान्वयन को समर्थन देने में मदद कर सकते है।

भाग–II बाहरी चुनौतियों से दृष्टि हटाकर आंतरिक परिवर्तन पर केंद्रित होता है और यह तर्क देता है कि भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता ऐसी संस्थागत प्रोत्साहन संरचना का निर्माण है जो अनिश्चितता की परिस्थितियों में कार्रवाई, प्रयोग और सीखने को प्रोत्साहित करे। यहाँ राज्य क्षमता को किसी एकल सुधार एजेंडा के रूप में नहीं, बल्कि एक संयोजित परिणाम के रूप में देखा जाता है, जो इस बात से निर्मित होता है कि निर्णय कैसे लिए जाते हैं, जोखिम और विफलता को कैसे समझा और संभाला जाता है, प्रशासन को परिणामों के इर्द-गिर्द कैसे संगठित किया जाता है, विनियमन का ढाँचा कैसे तैयार किया जाता है और उसे कैसे लागू किया जाता है, तथा प्रोत्साहन

किस प्रकार अधिकारियों, उद्यमों और नागरिकों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। नौकरशाही की जोखिम-निरोधक प्रवृत्ति, खंडित जवाबदेही, प्रक्रियात्मकता और वार्ता-आधारित शासन राज्य की निर्णायक और अनुकूलनशील ढंग से कार्य करने की क्षमता को कमजोर करते हैं। साथ ही, अध्याय इस बात पर जोर देता है कि क्षमता सह-उत्पादित होती है : अर्थात् कंपनियाँ और नागरिक भी यह निर्धारित करते हैं कि राज्य को क्षमता की दिशा में प्रेरित किया जाए या विवेकाधीनता और प्रवर्तन-केंद्रित शासन की ओर खींच लिया जाए।

यह अध्याय राज्य क्षमता के व्यवहारिक अनुप्रयोग के एक उदाहरण के तौर पर चल रहे अनुपालन-घटाने और विनियमन-शिथिलीकरण (डीरिगुलेशन) की पहल की भी जाँच करता है। यहाँ विनियमन-शिथिलीकरण को नियमों से पीछे हटने के रूप में नहीं, बल्कि संस्थागत पुनर्संरेखण के रूप में देखा गया है—जिसके अंतर्गत प्रशासनिक प्रयासों को कम-मूल्य वाले निगरानी और नियंत्रण से हटाकर समन्वय, सुविधा-प्रदान और समस्या-समाधान की दिशा में स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से यह प्रदर्शित किया गया है कि किस प्रकार अनुशासित रूप से अवरोधों को हटाना राज्य की शक्ति और प्रभावशीलता को सुदृढ़ कर सकता है।

इन दोनों भागों को एक साथ देखने पर एक एकीकृत तर्क सामने आता है : भारत की वर्तमान व्यापक आर्थिक मजबूती को दीर्घकालिक सामरिक प्रभाव और लाभ में परिवर्तित करने की क्षमता इस बात पर निर्भर करेगी कि राज्य अनिश्चितता की परिस्थितियों में कितने प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है, क्रियान्वयन से कितना सीख सकता है, विभिन्न प्रणालियों के बीच कितना समन्वय स्थापित कर सकता है और समय के साथ अनुशासन को कितनी दृढ़ता से बनाए रख सकता है। इस अर्थ में, राज्य क्षमता वह आर्थिक आधारभूत अवसंरचना है जिस पर सामरिक लचीलापन निर्मित होता है, और वही वह मार्ग है जिसके माध्यम से सामरिक अपरिहार्यता को संभव बनाया जा सकता है।

सुखस्य मूलं धर्मः ।
धर्मस्य मूलं अर्थः ।
अर्थस्य मूलं राज्यः ॥

सुख का मूल है, धर्म।
धर्म का मूल है, अर्थ।
अर्थ का मूल है, राज्य।

—चाणक्य सूत्र

हम सफल रहे हैं

16.1. कोविड -19 महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अत्यंत सराहनीय रहा है। भारत की आर्थिक वृद्धि दरें आज विश्व के लिए ईर्ष्या का विषय हैं। आने वाले वित्तीय वर्ष में भी इस वृद्धि की निरंतरता बनी रहने की संभावना है। भारत की संभावित वृद्धि दर संभवत: बढ़कर लगभग 7.0 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच गई है। बैंकिंग प्रणाली अच्छी स्थिति में है। ऋण मध्यस्थता (क्रेडिट इंटरमीडिएशन) स्वस्थ बनी हुई है। निजी क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और निवेश कर रहा है, हालांकि इसमें और वृद्धि की गुंजाइश बनी हुई है। सकल पूँजी निर्माण (Capital Formation) का सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा 30 प्रतिशत से अधिक है। चालू खाता घाटा सहज रूप से निम्न स्तर पर है। विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त हैं। बाह्य प्रेषण (रेमिटेंस) मजबूत बने हुए हैं। कृषि क्षेत्र भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। मानसून अनुकूल रहा है और रबी फसल के बेहतर होने की उम्मीद है। ग्रामीण भावना उत्साहजनक है–ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक मजदूरी में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है और ग्रामीण उपभोग में वृद्धि हो रही है। इसके विपरीत, शहरी उपभोग अपेक्षाकृत अधिक सतर्क प्रतीत होता है, यद्यपि इसके प्रमाण मुख्यत: कथात्मक हैं। साथ ही, ऐसे विपरीत साक्ष्य भी उपलब्ध हैं जो एक अलग और अधिक आशावादी तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, विशेषकर इसलिए कि राज्यों द्वारा घरों को दी जाने वाली राजकोषीय अंतरण की राशि अब काफी बढ़ गई है।

16.2. सरकार ने अपनी ओर से बुनियादी ढाँचे में सार्वजनिक निवेश जारी रखा है और राज्यों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिसके तहत 50 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार किए हैं। चार श्रम संहिताएँ, जो नियोक्ताओं को लचीलापन और श्रमिकों को न्यायपूर्ण व्यवहार प्रदान करती हैं, नवम्बर 2025 में अधिसूचित की गईं। सरकार ने कई गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को भी निलंबित कर दिया है, जो समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक साबित हुए, क्योंकि उन्होंने बड़ी कंपनियों को संरक्षण तो दिया, लेकिन उनके संरक्षित होने के बदले में कोई दायित्व नहीं रखा, और इसका नुकसान डाउनस्ट्रीम उत्पादकों को उठाना पड़ा ।

16.3. फरवरी 2025 में सरकार ने व्यक्तियों के लिए न्यूनतम कर-सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया, जिससे परिवारों को उल्लेखनीय राहत प्रदान की गई। दो आय अर्जकों वाले किसी परिवार को लगभग 26.7 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर आयकर नहीं देना पड़ता। बीते एक वर्ष में खाद्य कीमतों में अत्यंत कम मुद्रास्फीति के साथ मिलकर, इस कदम ने परिवारों के हाथों में पर्याप्त उपभोग योग्य आय छोड़ी है। सितंबर में सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में एक दूरगामी सुधार लागू किया, जिसके अंतर्गत कर स्लैबों की संख्या को घटाकर दो कर दिया गया और अनेक वस्तुओं को निम्न दर वाले स्लैब में स्थानांतरित किया गया। इससे घरेलू क्रय-शक्ति में और वृद्धि हुई तथा मुद्रास्फीति में कमी आई। सरकार ने आयकर प्रावधानों और उनकी भाषा को भी सरल बनाया। इसके अतिरिक्त, फरवरी 2025 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार, बीमा क्षेत्र को विदेशी निवेशकों के लिए तथा परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र को निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिया गया।

16.4. इन सुधारात्मक पहलों के अतिरिक्त, सरकार ने राष्ट्रीय लचीलेपन को व्यवस्थित रूप से सुदृढ़

किया है। इसके लिए उसने महत्वपूर्ण खनिजों और सेमीकंडक्टरों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु निवेश किया है, साथ ही जहाज निर्माण उद्योग को निरंतर और सतत प्रयासों के माध्यम से समर्थन प्रदान किया है। इन विषयों का विस्तृत विवरण क्रमशः अध्याय 8, 9 और 10 दिया गया है।

16.5. इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि अप्रैल और अगस्त में अमेरिका सरकार द्वारा भारत पर क्रमशः पारस्परिक शुल्क और दंडात्मक शुल्क लगाए जाने के अप्रत्याशित घटनाक्रम के बाद, भारत सरकार ने भारतीय निर्यातकों के लिए अधिक बाजार खोलने हेतु अन्य देशों के साथ वार्ताओं को तीव्र कर दिया। सरकार ने निर्यातकों के लिए एक राहत पैकेज को भी मंजूरी दी और नई भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तार को समर्थन देने के लिए पाँच वर्षीय निर्यात संवर्धन पैकेज की घोषणा की।

16.6. सरकार के सुव्यवस्थित और अत्यंत लक्षित प्रयासों के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था निरंतर वृद्धि के लिए अच्छी स्थिति में है। व्यापक वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी संभावनाएँ अच्छी दिख रही हैं, जो और भी अधिक सराहनीय है।

विश्व परिवेश के बारे में आश्वस्ति कम है, अनिश्चितता अधिक है।

16.7. वैश्विक अनिश्चितताएँ न केवल व्यापक हैं, बल्कि गहराई से संरचनात्मक भी हैं। अच्छी हो या बुरी, युद्ध के समाप्त होने के बाद से लगभग साढ़े पाँच दशकों तक जो वैश्विक क्रम चला था, वह नई सदी में बिखरने लगा। पहला चेतावनी संकेत शुरुआती 2000 के दशक में दूरसंचार, मीडिया और प्रौद्योगिकी (टीएमटी) तथा इंटरनेट बुलबुले के अंत के साथ मिला। चीन ने 2001 में विश्व व्यापार संगठन (WTO) में प्रवेश किया और अगले दो दशकों में वैश्विक निर्माण और निर्यात शक्ति बन गया, जिससे विकसित और विकासशील देशों में विनिर्माण और निवेश की स्थिति अस्थिर हो गई। फिर एक बड़ा संकट आया - 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट। इसने अमेरिका के वित्तीय क्षेत्र को लगभग ध्वस्त कर देने की स्थिति पैदा कर दी और 1980 के दशक से अपनाए जा रहे पोस्ट-इंडस्ट्रियल वित्तीयकरण-आधारित विकास के अमेरिकी मॉडल तथा अमेरिकी डॉलर पर दुनिया के भरोसे को गंभीर रूप से आघात पहुँचाया।

16.8. विकसित विश्व में नीति-निर्माताओं की प्रतिक्रिया यह रही कि उन्होंने दीर्घ अवधि तक समग्र माँग को स्थिर करने के लिए अल्पकालिक मौद्रिक नीति उपकरणों का उपयोग किया। नीतिगत दरों को शून्य तक घटा दिया गया और दीर्घकालिक दरों को केंद्रीय बैंकों द्वारा सरकारी बॉन्ड की सक्रिय खरीद के माध्यम से निम्न स्तर पर बनाए रखा गया। इन कार्रवाइयों ने उनकी अर्थव्यवस्थाओं को और अधिक वित्तीय-केंद्रित बना दिया तथा विनिर्माण-केन्द्रित समुदायों को सामाजिक और आर्थिक व्यवधानों के प्रति असुरक्षित बना दिया।

16.9. 2020 में COVID-19 के प्रकोप और इसके कारण उत्पन्न व्यवधानों ने दुनिया भर में आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को और भी बढ़ा दिया। वैश्विक स्तर पर, महामारी से निपटने के लिए उठाए गए नीतिगत कदमों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र का ऋण काफी बढ़ गया है। चीन का विनिर्माण निर्यात शक्ति के रूप में उभार, बढ़ता ऋण, मध्यम वर्ग की बढ़ती असंतुष्टि और घटती वृद्धि ने पश्चिमी देशों में

राजनीतिक बदलावों को जन्म दिया है, जिससे 1980 के दशक से प्रचलित अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की नींव हिल गई है।

16.10. पूर्वदर्शिता के साथ, फरवरी 2020 में, कोविड-19 महामारी फैलने के तुरंत बाद, फंड मैनेजर अल्बर्टो गैलो ने चेतावनी दी थी कि 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद अपनाई गई असाधारण मौद्रिक शिथिलीकरण–और महामारी के प्रति और भी आक्रामक प्रतिक्रिया–उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को अत्यंत ढीली मौद्रिक स्थितियों के लंबे चरण में फँसाने का जोखिम रखती है। एक दशक तक मात्रात्मक सहजता और नॉमिनल तथा वास्तविक ब्याज दरों में लगातार गिरावट के बाद, उन्होंने तर्क दिया कि मौद्रिक नीति उत्पादक निवेश को प्रोत्साहित करने में अपनी प्रभावशीलता खो रही है। इसके बजाय, तरलता ब्याज-दर-संवेदनशील और सुरक्षित परिसंपत्तियों में प्रवाहित हो रही है, जिससे परिसंपत्ति मूल्यों में वृद्धि हो रही है और वास्तविक प्रतिफल संकुचित हो रहे हैं। उन्होंने इस गतिशीलता को "क्यूई इन्फिनिटी ट्रैप" कहा, जिसमें अर्थव्यवस्थाएँ केवल आर्थिक गतिविधि बनाए रखने के लिए निरंतर सहजता पर निर्भर हो जाती हैं। इस पूर्वानुमान के कई तत्व अब स्पष्ट रूप से सामने आ चुके हैं। विकसित विश्व के अधिकांश हिस्सों में वित्तीय दमन और नकारात्मक वास्तविक प्रतिफल देखने को मिले हैं, जबकि भू-राजनीतिक तनाव, व्यापारिक घर्षण और संघर्षों ने वैश्विक परिदृश्य को और अधिक अनिश्चित तथा नाजुक बना दिया है। इस सबके साथ, विश्व असुरक्षा, अप्रत्याशितता और जोखिम के दौर में प्रवेश कर गया है। अमेरिका में नई प्रशासन व्यवस्था भी अपनी साझेदारियों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन कर रही है और उन्हें पुनः विन्यस्त कर रही है। अब व्यापार बहुपक्षीय समझौतों के बजाय द्विपक्षीय समझौतों का विषय बन गया है। देश पड़ोसी को नुकसान पहुँचाने वाली व्यापार नीतियों (बेगगर-थाय-नेबर) को अपनाने लगे हैं, और निर्यात लाइसेंसिंग अब अपवाद की बजाय सामान्य नियम बन गया है।

चार्ट XVI.1: मात्रात्मक शिथिलीकरण का अनंत जाल (क्यूई इन्फिनिटी ट्रैप)

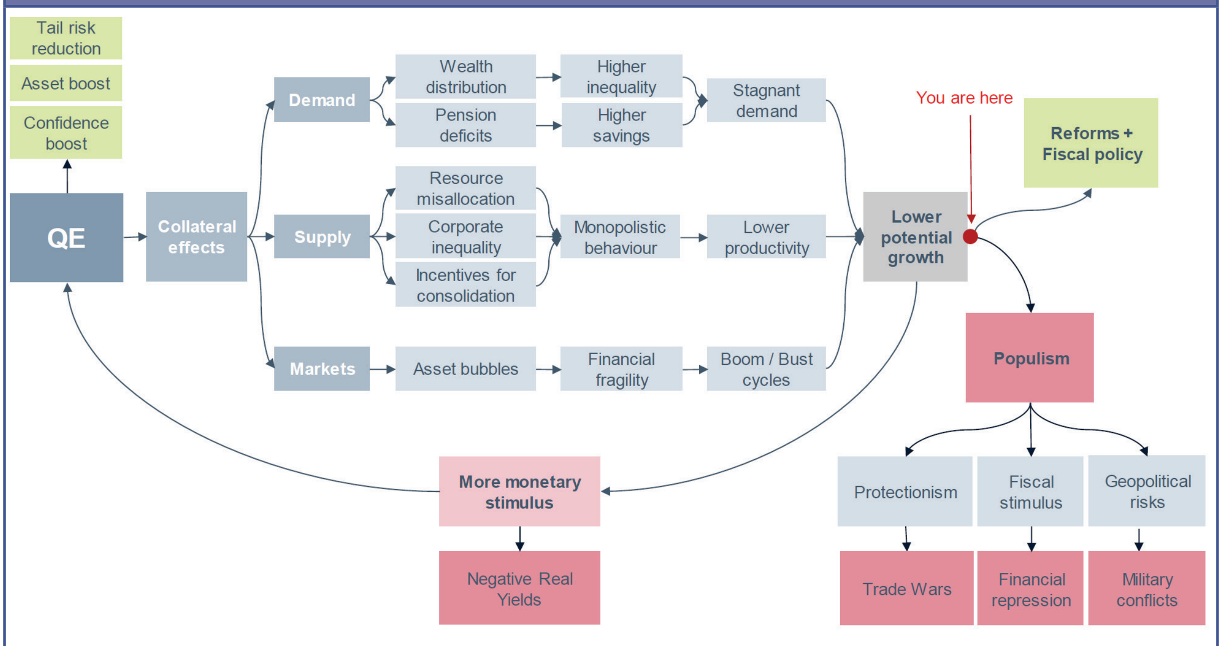

स्रोतः अल्बर्टो गैलो, अल्गेब्रिस इन्वेस्टमेंट्स, फरवरी 2020।

16.11 इसी बीच, पहले टेक्नोलॉजी बबल के समाप्त होने के दो दशक से अधिक समय बाद, अमेरिका और दुनिया के कुछ हिस्से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में आए उछाल पर बड़ा दांव लगा रहे हैं, जो हमारे काम करने, खुद को सुरक्षित रखने और सीखने-सिखाने के तरीकों को नया आकार दे रहा है। जहाँ तकनीकी आशावाद आगे बढ़ता है, वहाँ वित्तीय अभियांत्रिकी उसका अनुसरण करती है। इस स्थिति में, इतिहास केवल तुकबंदी नहीं कर रहा बल्कि स्वयं को दोहराता प्रतीत होता है। वर्तमान में, एआई का विकास संसाधन-प्रधान मार्ग पर आगे बढ़ा है। ऊर्जा माँग में यह तीव्र वृद्धि प्रमुख क्षेत्रों में डाटा केंद्रों द्वारा बिजली खपत में अनुमानित तेज बढ़ोतरी में परिलक्षित होती है (चार्ट XVI.2)। विद्युत ग्रिड अस्थिर हो गए हैं, बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है और ऊर्जा लागत में वृद्धि हुई है– जिसे सौर और पवन जैसी अंतरालिक ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ते झुकाव ने और जटिल बना दिया है। मितव्ययी एआई संभव हो सकता है, किंतु वह अभी क्षितिज पर नहीं है, न ही वह फिलहाल वाणिज्यिक या वैश्विक स्तर पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी संघीय सरकार ने राज्यों को एआई के विनियमन से रोक दिया है।

चार्ट XVI.2: डाटा सेंटर्स द्वारा बिजली की खपत में अनुमानित बढ़ोतरी

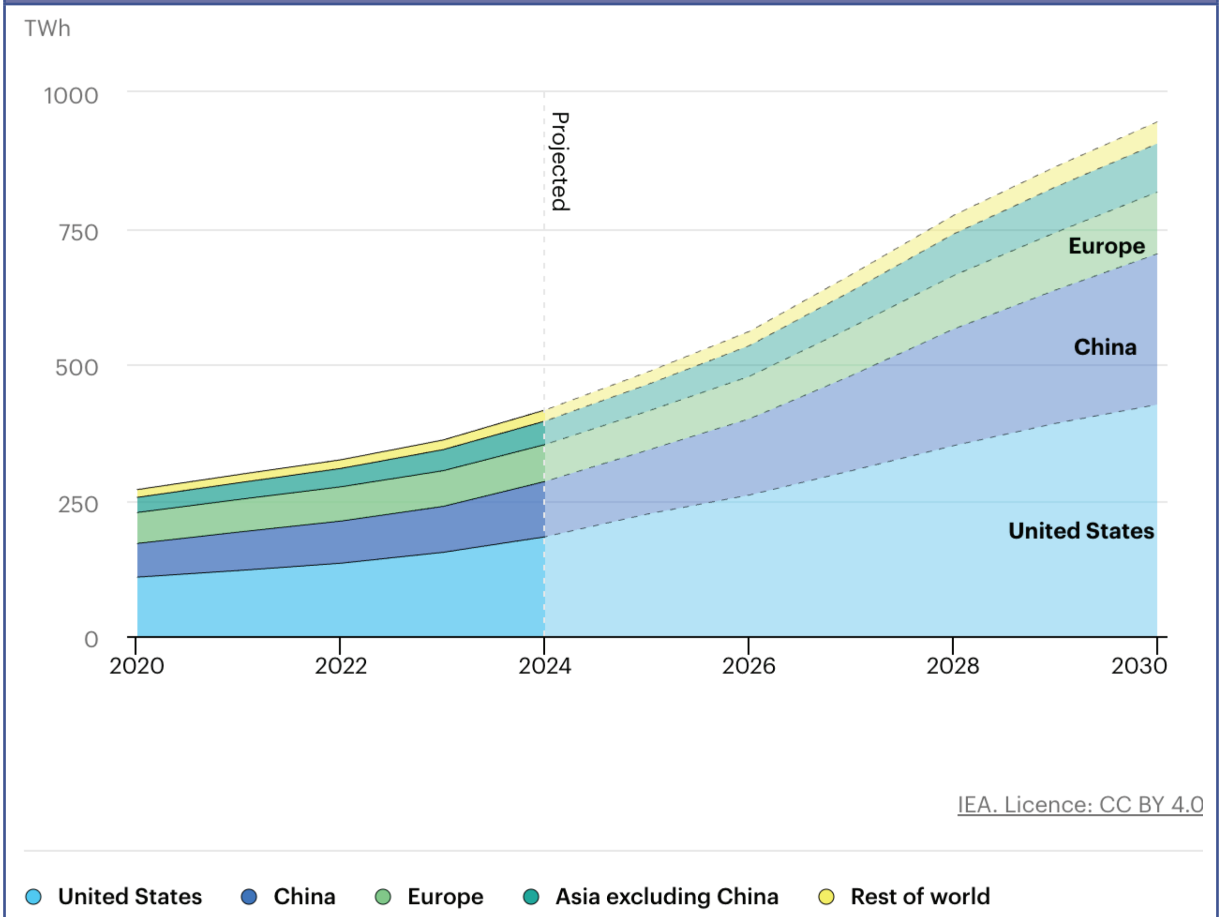

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)[1]।

1 अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA): क्षेत्रवार डाटा केंद्रों की विद्युत खपत, आधार परिदृश्य (2020–2030)। https://tinyurl.com/4fc63kk5

संकीर्ण और संकुचित होते गठबंधन

16.12. बिजली की माँग में तेजी ने ताँबे की माँग में भी समान रूप से वृद्धि कर दी है। वर्ष 2025 में ताँबे की कीमतें लगभग पाँचवें हिस्से तक बढ़ गई हैं (चार्ट XVI.3), जबकि इसी अवधि में प्रतिफल में गिरावट आई है। केवल महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों ही नहीं, बल्कि मौलिक धातुएँ भी बढ़ती माँग और सख्त होती आपूर्ति के कारण आपूर्ति बाधाओं का सामना करेंगी–जहाँ ये बाधाएँ प्राकृतिक कारणों के साथ-साथ राष्ट्रीयतावादी नीतिगत कारणों से भी उत्पन्न होंगी।

चार्ट XVI.3 बढ़ती माँग के बीच तांबे की कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचीं

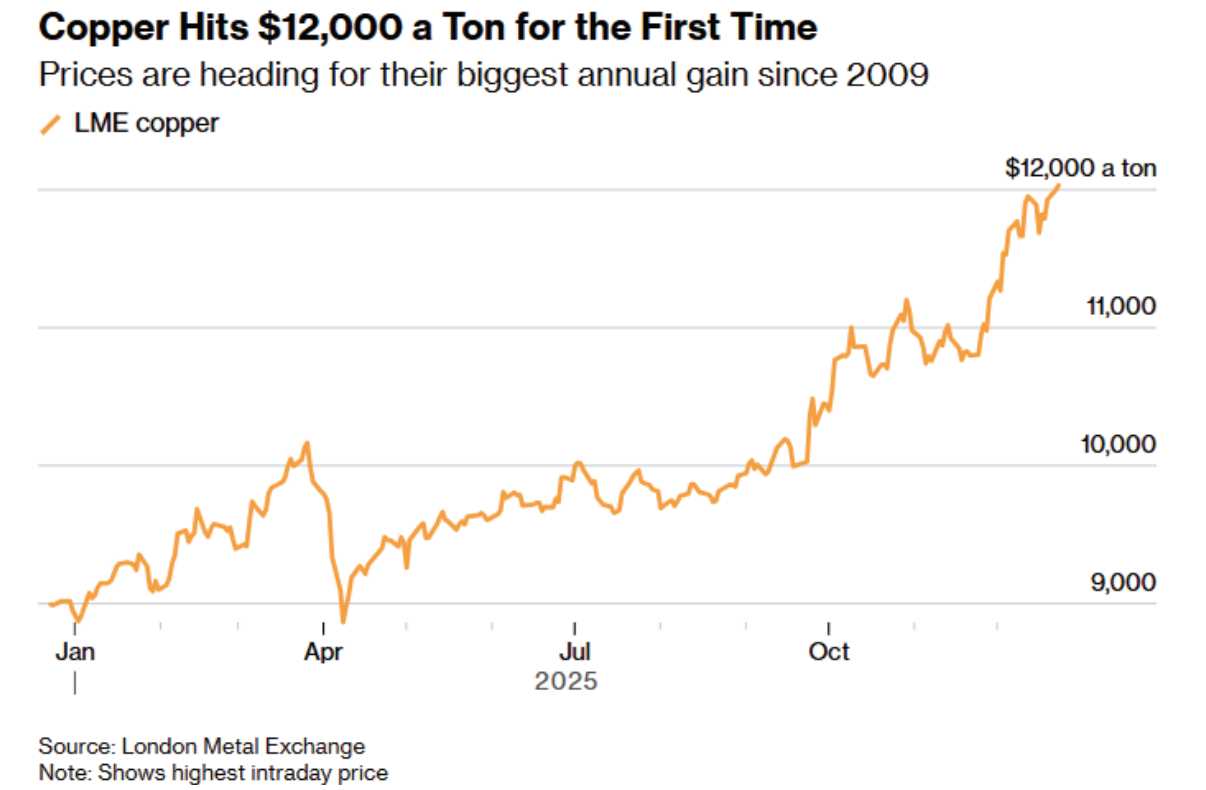

स्रोत: ब्लूमबर्ग[2]

16.13. यह कहते हुए कि 20वीं सदी तेल और इस्पात पर आधारित थी और 21वीं सदी 'कम्प्यूट'–अर्थात् संगणन शक्ति या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPU)– और उन्हें पोषित करने वाले खनिजों पर आधारित होगी, अमेरिका ने कुछ समान सोच वाले देशों के साथ मिलकर पैक्स सिलिका घोषणा[3] की। इसका उद्देश्य ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों से लेकर उच्च-स्तरीय विनिर्माण और एआई मॉडलों तक, भविष्य के कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पारितंत्र का निर्माण करना है।

16.14. इसी बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जुलाई 2025 में जीनियस अधिनियम (Guiding and Establishing National Innovation वित U.S. Stablecoins Act) पारित किया, जो जनवरी 2027

2 मार्क बर्टन और जेम्स एटवुड। ब्लूमबर्ग। 23 दिसंबर 2025। https://tinyurl.com/375y6tv4

3 स्रोत: अमेरिकी विदेश विभाग, पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन, 11 दिसंबर 2025। https://www.state.gov/releases/2025/12/pax-silica-initiative/

से अथवा इसके कार्यान्वयन से संबंधित नियम जारी होने के 120 दिनों बाद–जो भी पहले हो–प्रभाव में आएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत[4] विनियमित निजी क्षेत्र की संस्थाओं को अमेरिकी डॉलर-समर्थित स्टेबलकॉइन जारी करने की अनुमति दी जाएगी। इस पहल की सफलता के स्तर पर निर्भर करते हुए, इसमें उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की ओर जाने वाले पूँजी प्रवाह को बाधित या पुनर्संरचित करने की क्षमता निहित है।

16.15. भारत ने पिछले एक दशक में अपने बाह्य खातों का विवेकपूर्ण ढंग से प्रबंधन किया है। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है, बाह्य ऋण प्रबंधनीय बना हुआ है और संकट के दौरों को प्रणालीगत पतन के बिना संभाला गया है। ये उपलब्धियाँ सुदृढ़ व्यापक आर्थिक प्रबंधन को दर्शाती हैं। फिर भी, स्थिरता का स्रोत महत्त्वपूर्ण है। भारत की बाह्य वित्तपोषण का बड़ा हिस्सा पोर्टफोलियो प्रवाह, ऋण प्रवाह और विदेशी निवेश की आवधिक तीव्र आवक के माध्यम से आया है। ये प्रवाह मूल्यवान अवश्य हैं, किंतु सशर्त और प्रत्यावर्तनीय होते हैं। ये न केवल घरेलू आधारभूत कारकों पर, बल्कि वैश्विक तरलता चक्रों, जोखिम-भावना और भारत के नियंत्रण से बाहर भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर भी प्रतिक्रिया करते हैं। मुख्यतः पूँजी प्रवाह पर आधारित मुद्राएँ, तनाव की स्थितियों में, उन मुद्राओं से भिन्न व्यवहार करती हैं जो निरंतर निर्यात अधिशेष द्वारा समर्थित होती हैं। वैश्विक जोखिम-परिहार की परिस्थितियों में पूंजी का प्रत्यावर्तन होता है। विनिमय दरें समय के साथ समायोजित होती हैं–और कभी-कभी यह समायोजन अचानक भी होता है। केंद्रीय बैंक अस्थिरता को कुछ हद तक समतल कर सकते हैं, परंतु भंडार संचय या ब्याज दरों में समायोजन के माध्यम से संरचनात्मक असंतुलनों की स्थायी भरपाई नहीं कर सकते। यही वह कठोर बाधा है जो भारत की व्यापक आर्थिक आकांक्षाओं के समक्ष खड़ी है और भारत इस वर्ष पहले ही इसके प्रभाव को महसूस कर चुका है।

16.16. उच्च बाजार मूल्यांकन और भारत-अमेरिका संबंधों की दीर्घकालिक दिशा को लेकर उठे प्रश्न – जिनका कारण अमेरिका द्वारा भारत पर उच्च शुल्क लगाना और पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना रहा–ने पोर्टफोलियो निवेशकों को लाभ बुक करने और प्रतीक्षा की स्थिति में रहने के लिए प्रेरित किया। यद्यपि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में सुधार हुआ है, वे बड़े पैमाने पर हुए पोर्टफोलियो बहिर्प्रवाह की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं रहे। इसके अतिरिक्त, बढ़ती व्यापारिक पाबंदियों के कारण भारतीय कंपनियों को अन्य देशों में निवेश करने के लिए भी विवश होना पड़ा है। स्थानीय स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक हो गया है ताकि स्थानीय स्तर पर बिक्री की जा सके। भारत समग्र रूप से व्यापार घाटे की स्थिति में है, क्योंकि सेवाओं के व्यापार में प्राप्त अधिशेष वस्तुओं के व्यापार में हुए घाटे की भरपाई नहीं कर पाता और प्रेषण तथा शुद्ध अदृश्य मद भी पर्याप्त नहीं हैं। परिणामस्वरूप, भारत अपने आयातों के वित्तपोषण के लिए वैश्विक पूँजी प्रवाह पर निर्भर रहता है। जब ये प्रवाह आवश्यक स्तर तक साकार नहीं हो पाते, तो मुद्रा पर अवमूल्यन का दबाव उत्पन्न होता है। भू-राजनीतिक संघर्षों के उभरने के साथ ही 'वैश्विक पूँजी हड़ताल' का जोखिम नगण्य नहीं रह जाता। पूँजी-आयात पर निर्भर देश के रूप में भारत इस असुरक्षा की अग्रिम पंक्ति में स्थित है।

4 संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिनिधि सभा की वित्तीय सेवाएँ समिति। जुलाई 2025। यू.एस. स्टेबलकॉइन्स हेतु राष्ट्रीय नवाचार का मार्गदर्शन और स्थापना अधिनियम (जीनियस अधिनियम): अनुभागवार सारांश। https://tinyurl.com/2x9az5bm

आगे और भी अनिश्चितताएँ हैं

16.17. जैसे ही वर्ष 2025 समाप्ति की ओर बढ़ा, चीन ने हैनान द्वीप के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। हैनान मुक्त व्यापार बंदरगाह (एफटीपी) चीन का साहसिक प्रयोग है, जिसके माध्यम से वह अपनी अर्थव्यवस्था को मुख्यभूमि के अन्य हिस्सों की तुलना में कहीं अधिक व्यापक रूप से खोल रहा है। यह केवल एक शहर या छोटा क्षेत्र नहीं है, बल्कि पूरे हैनान द्वीप प्रांत को एक विशेष व्यापार और व्यवसाय क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया है, जहाँ व्यापार, सीमा शुल्क, कर, निवेश और वीजा पर अत्यंत उदार नियम लागू किए गए हैं।

16.18. सरल शब्दों में, अधिकांश आयातों पर शुल्क हटा दिए गए हैं, जिससे विदेश से आने वाले सामान बिना सीमा शुल्क के द्वीप में प्रवेश कर सकते हैं। यह द्वीप मुख्य भूमि चीन से अलग एक विशेष सीमा शुल्क प्रणाली के तहत संचालित होता है। हैनान में निर्मित वे वस्तुएँ, जिनमें वास्तविक मूल्य संवर्धन हुआ हो (जैसे कम से कम 30% स्थानीय प्रसंस्करण), यदि निर्धारित नियमों का पालन करती हैं जो वास्तविक उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं और केवल पुनः निर्यात को नहीं, तो उन्हें चीन के अन्य हिस्सों में अतिरिक्त शुल्क के बिना बेचा जा सकता है। द्वीप के भीतर वस्तुओं, लोगों, पूँजी और सेवाओं का प्रवाह न्यूनतम बाधाओं के साथ स्वतंत्र रूप से होता है। यह आधिकारिक रूप से 18 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ, जब हैनान की पूर्ण-द्वीप सीमा शुल्क संचालन प्रारंभ हुआ, जिससे यह एक कार्यशील मुक्त व्यापार बंदरगाह बन गया।

16.19. भारत के लिए, हैनान का मुक्त व्यापार बंदरगाह किसी एक बड़े विघटनकारी झटके के रूप में नहीं, बल्कि एक क्रमिक संरचनात्मक विकास के रूप में समझा जाना चाहिए, जो चीन के निकटवर्ती क्षेत्र में व्यापार, लॉजिस्टिक्स और निवेश की अर्थव्यवस्था को सूक्ष्म रूप से बदलता है। व्यावहारिक रूप से, यह भारतीय महासागर के उत्तरी हिस्सों और दक्षिण चीन सागर में एक विशाल, कम-शुल्क, सेवाओं-प्रधान आर्थिक क्षेत्र का निर्माण करता है, जो समय के साथ आपूर्ति-श्रृंखला मार्ग निर्धारण, पर्यटन प्रवाह और एशिया में कॉर्पोरेट निवेश निर्णयों के पैटर्न को प्रभावित कर सकता है।

16.20. इस विकास का महत्व केवल उस निवेश प्रतिस्पर्धा में नहीं है जिसे यह उत्पन्न करता है, बल्कि उस वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी है जिसमें यह घटित हो रहा है – एक ऐसा परिप्रेक्ष्य जो लगातार अधिक अस्थिर होता जा रहा है। उत्पादन, पूँजी और आपूर्ति-श्रृंखलाओं से संबंधित निर्णय अब विश्व अर्थव्यवस्था की व्यापक नाजुकता की भावना के साथ और अधिक उलझते जा रहे हैं।

16.21. जब हम यह अध्याय लिख रहे हैं[5], तब प्रारंभिक धारणा यह होने के बावजूद कि वैश्विक अर्थव्यवस्था ने 2025 के झटकों को अपेक्षा से बेहतर ढंग से सहन किया है, स्थिति अब भी नाजुक बनी हुई है। इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और फाइनेंशियल मार्केट के मामले में 'बिजनेस एज यूजुअल' (BAU) या 'जैसे-तैसे काम चलाने' के पारंपरिक तरीके अब खत्म हो सकते हैं। वैश्विक मामलों में मध्यम से गंभीर व्यवधान या कोई बड़ा टूटाव होने की संभावना, बीएयू परिदृश्य की तुलना में अधिक है। वैश्विक

5 यह हम 3 जनवरी 2026 को लिख रहे थे, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला में सफल शासन परिवर्तन की घोषणा की थी।

पूँजी प्रवाह पर निर्भर देश होने के नाते, भारत को आने वाले वर्ष में तरलता और बाह्य पूँजी भंडार की योजना बनानी होगी। पूँजी पलायन, विशेषकर अमेरिकी स्टेबलकॉइन्स के आगमन के साथ, एक और जोखिम है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। भारत अधिकांश देशों की तुलना में संतोषजनक वृद्धि दर बनाए रखने की स्थिति में बेहतर रहेगा, लेकिन इसके लचीलेपन पर परीक्षा होगी, क्योंकि पूँजी, ऊर्जा और अन्य महत्वपूर्ण इनपुट जैसे उर्वरक के लिए बाहरी निर्भरता के कारण सामरिक संवेदनशीलताएँ बनी हुई हैं।

16.22 भविष्य की ओर देखें तो, भारत को दीर्घकालिक भू–राजनीतिक अनिश्चितताओं और संघर्षों के लिए तैयार रहना होगा, साथ ही विकसित समाजों में उत्पन्न होने वाले परिणामी व्यवधानों से भी निपटने की तैयारी करनी होगी। यह पूरी तरह संभव है कि अब से 2045 तक का काल बीसवीं शताब्दी के अंतरयुद्ध वर्षों जैसा प्रतीत हो। निस्संदेह, 1930 के दशक में, महामंदी और युद्ध की शुरुआत के बीच अनेक नवाचार हुए।[6] स्वयं युद्ध ने औद्योगिक क्षमता के विकास में योगदान दिया, जिसने बाद में वैश्विक अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचाया। लेकिन ऐसे अशांत काल में जीवित रहने और आवश्यकताओं को नवाचारों में बदलने के लिए केवल रक्षात्मक नहीं, बल्कि सक्रिय और आक्रामक नीतिगत ढाँचे की आवश्यकता होती है। वास्तव में, एक अधिक अनिश्चित और सामरिक रूप से विवादित विश्व की रूपरेखा पहले से ही उस अंतरराष्ट्रीय आर्थिक वातावरण में दिखाई दे रही है जिसका सामना भारत आज कर रहा है।

16.23 आज भारत जिस वैश्विक आर्थिक वातावरण का सामना कर रहा है, वह पिछली वैश्वीकरण की अवस्था से भिन्न है। शीत युद्ध के बाद की अवधि को आकार देने वाले अनुमान – जैसे खुला व्यापार, पूर्वानुमेय नियम, स्थिर पूँजी प्रवाह और अपेक्षाकृत गैर–राजनीतिक परस्पर निर्भरता – अब उतने दृढ़ नहीं रहे। व्यापार, प्रौद्योगिकी, वित्त और आपूर्ति–श्रृंखलाएँ अब बढ़ते हुए सामरिक विचारों से प्रभावित हो रही हैं। इस परिप्रेक्ष्य में परिणाम केवल व्यापक आर्थिक स्थिरता या कारक संचय पर ही नहीं, बल्कि संस्थागत और सामरिक क्षमता पर भी निर्भर करते हैं।

16.24. संस्थागत और सामरिक क्षमताओं का निर्माण समय लेता है। इसके लिए धैर्यपूर्वक संस्थाओं का निर्माण आवश्यक है, ऐसी कंपनियाँ चाहिए जो प्रतिस्पर्धा करें न कि संरक्षण पर निर्भर रहें और ऐसे नागरिक चाहिए जो नियमों को आंतरिक रूप से स्वीकार करें, न कि उन्हें केवल सौदेबाजी योग्य मानें। क्षमता–निर्माण में गति और धैर्य, संरक्षण और प्रतिस्पर्धा तथा स्वायत्तता और एकीकरण के बीच संतुलन साधने जैसे समझौते शामिल होते हैं। इन्हें टाला नहीं जा सकता, केवल प्रबंधित किया जा सकता है।

16.25. यह परिदृश्य दर्शाता है कि अब प्रमुख विनिर्माण शक्तियाँ स्वयं व्यापार को किस दृष्टि से देखती हैं, उसमें एक गहरा परिवर्तन आया है।[7] विशेष रूप से चीन व्यापार को परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं के बीच पारस्परिक विनिमय के रूप में नहीं, बल्कि उत्पादन प्रभुत्व की दीर्घकालिक रणनीति में एक संक्रमणकालीन चरण के रूप में देखता है वह दुनिया भर में अपना सामान बेचना चाहता है, और साथ ही वह धीरे–धीरे अपनी बाहरी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करता जा रहा है। ऐसे परिदृश्य में खुलापन

6 मॉर्गन हाउस देखें https://collabfund.com/blog/careful-what-you-wish-for/, April 2017.

7 रॉबिन हार्डिंग, फाइनेंशियल टाइम्स, 26 नवम्बर 2025। चीन व्यापार को असंभव बना रहा है। https://tinyurl.com/ykhfyhbn

असममित बन जाता है—जहाँ कुछ देश बाहरी बाजारों और इनपुट्स के प्रति संवेदनशील बने रहते हैं, जबकि अन्य देशों के पास सीमित लागत में पहुँच प्रतिबंधित करने की क्षमता बनी रहती है।

स्वदेशी अपरिहार्य और आवश्यक है

16.26. ऐसे विश्व में जहाँ आर्थिक संबंध दिन-ब-दिन सामरिक और विवादित होते जा रहे हैं, वहाँ चयनात्मक रूप से सीखने की क्षमता राज्य संचालन का एक मुख्य तत्व बन जाती है। महाकाव्य रामायण इस संदर्भ में जटिल और विवादित परिस्थितियों में सामरिक सीख का एक मूल्यवान रूपक प्रस्तुत करता है। युद्ध कांड में, रावण की हार का पल समझदारी का सबक बन जाता है, क्योंकि भगवान राम दिखाते हैं कि सूझ-बूझ और ज्ञान दुश्मनों से भी लिया जा सकता है, बिना उनके मूल्यों या तरीकों को अपनाए। यह सीख बारीक लेकिन असरदार है : सीखना स्वायत्तता के साथ संगत हो सकता है। आज की खंडित वैश्विक अर्थव्यवस्था में, निर्भरता से मुक्त सीखने की क्षमता एक अनिवार्य सामरिक कौशल बन चुकी है।

16.27. सामरिक परिप्रेक्ष्य इस तरह बदल गया है कि अब खुलेपन का गणित मौलिक रूप से बदल गया है। निर्यात नियंत्रण, प्रौद्योगिकी निषेध व्यवस्थाएँ, कार्बन सीमा तंत्र और औद्योगिक नीतियाँ—चाहे पश्चिम में हों या पूर्व में—यह संकेत देती हैं कि अब सहज वैश्वीकरण का युग समाप्त हो गया है। हम ऐसे वातावरण में कार्य कर रहे हैं जहाँ इनपुट्स, प्रौद्योगिकियों और बाजारों तक पहुँच को सहज या स्थायी मान लेना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में स्वदेशी न केवल रक्षात्मक, बल्कि आक्रामक नीति उपकरण भी बन जाता है। यह बाहरी झटकों के समय उत्पादन की निरंतरता सुनिश्चित करने का साधन है और दीर्घकालिक राष्ट्रीय क्षमताएँ विकसित करने का मार्ग है, जो आर्थिक संप्रभुता को सुदृढ़ करती हैं। नीति का प्रश्न अब यह नहीं है कि क्या राज्य स्वदेशी को प्रोत्साहित करे, बल्कि यह है कि कैसे इसे इस तरह लागू किया जाए कि दक्षता, नवाचार और वैश्विक एकीकरण को कमजोर न किया जाए।

16.28. सभी प्रकार के आयात प्रतिस्थापन वांछनीय नहीं होते और सभी प्रकार की संरक्षणवादी नीतियाँ दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता का समर्थन नहीं करतीं। स्वदेशी-उन्मुख नीतियों के प्रति सबसे स्थायी आपत्ति वैचारिक नहीं बल्कि अनुभवजन्य है। भारत का अपना इतिहास, जैसे कई अन्य विकासशील देशों का पर्याप्त उदाहरण प्रस्तुत करता है जहाँ संरक्षण ने आत्मसंतोष को जन्म दिया, अक्षमता को गहराई दी और कंपनियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा से अलग-थलग कर दिया। स्वदेशी एक अनुशासित रणनीति है, न कि एक सर्वव्यापी सिद्धांत।

16.29. आयात प्रतिस्थापन तब उचित ठहराया जा सकता है जब घरेलू उत्पादन पहले से ही उचित लागत पर संभव हो, लेकिन गैर-आर्थिक कारकों—जैसे समन्वय विफलताएँ या पुरानी नियामकीय बाधाएँ—के कारण बाधित हो रहा हो। यह तब भी उचित है जब अस्थायी और स्पष्ट रूप से समय-सीमित संरक्षण सीखने, पैमाना बनाने और उत्पादकता लाभ को सुगम बना सके; जब संरक्षित उद्योग निर्यात अनुशासन और मापनीय प्रदर्शन मानकों के अधीन हो; और जब संबंधित वस्तु सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हो, भले ही लागत संबंधी प्रतिकूलताएँ बनी रहें। ये शर्तें बुद्धिमान आयात प्रतिस्थापन (सशर्त संरक्षण) को घरेलू कंपनियों को अंधाधुंध संरक्षण देने से अलग करती हैं।

16.30. इसका विपरीत भी सत्य है : स्थायी संरक्षण उन क्षेत्रों में अनुचित है जहाँ भारत पहले से ही लागत-प्रतिस्पर्धी है, जहाँ बड़े पैमाने पर निर्यात किया जा रहा है, जहाँ उत्पाद आपूर्ति-श्रृंखलाओं में सामान्य प्रयोजन मध्यवर्ती के रूप में काम करते हैं, या जहाँ इनपुट श्रम-प्रधान उद्योगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ऐसे मामलों में संरक्षण पूरे अर्थतंत्र की लागत बढ़ाने, प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करने और निर्यात क्षमता को कमजोर करने का जोखिम पैदा करता है। इसी प्रकार, हमें ऐसी संरक्षणात्मक नीतियों के प्रति भी सतर्क रहना चाहिए जो निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करे, विपरीत शुल्क संरचनाओं के माध्यम से स्थापित हितों को सुदृढ़ कर दे, अथवा समर्थन को नवाचार, सीखने की प्रक्रिया और वैश्विक एकीकरण से अलग कर दे। मुख्य निष्कर्ष यह है कि उत्पादकता-वर्धक निवेश, क्षमता उन्नयन और निर्यात-उन्मुखता के बिना संरक्षण शक्ति नहीं बल्कि दुर्बलता पैदा करता है।

16.31. स्वदेशीकरण के प्रति एक अनुशासित दृष्टिकोण के लिए यह स्पष्टता आवश्यक है कि हस्तक्षेप कब दीर्घकालिक क्षमता का निर्माण करता है और कब वह केवल अक्षमता को बनाए रखता है। नीचे एक सरल निर्णय ढाँचा प्रस्तुत किया गया है, जो खंडित वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्वदेशीकरण और सुरक्षा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस ढांचे का उद्देश्य सामान्य रूप से हस्तक्षेप को उचित ठहराना नहीं, बल्कि इसे अनुशासित करना है। यह ढाँचा इस प्रकार आगे बढ़ता है कि वह यह पहचान करता है कि कहाँ हस्तक्षेप उचित हो सकता है, यह स्पष्ट करता है कि कहाँ हस्तक्षेप से बचना चाहिए, और क्रमबद्धता, सशर्तता तथा निर्यात-उन्मुखता के माध्यम से अनुशासन को अंतर्निहित करता है।

16.32 व्यवहार में, इस ढाँचे का अनुप्रयोग भिन्न-भिन्न प्राथमिकताओं को उत्पन्न करता है। कुछ इनपुट प्रणालीगत रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और वैश्विक आपूर्ति के संकेंद्रण या सामरिक जोखिम के कारण प्रारंभिक ध्यान के पात्र होते हैं। अन्य इनपुट आर्थिक रूप से घरेलू क्षमता-निर्माण के लिए उपयुक्त उम्मीदवार होते हैं, जहाँ पैमाना, सीखने और निर्यात-उन्मुखता के माध्यम से समय के साथ प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त की जा सकती है। तीसरी श्रेणी उन वस्तुओं की है जिनमें आयात-निर्भरता असुरक्षा में परिवर्तित नहीं होती और जहाँ घरेलू प्रतिस्थापन लागत बढ़ा सकता है लेकिन लचीलापन नहीं बढ़ाता। नीचे प्रस्तुत स्तरीकृत ढाँचा इस भिन्नता को औपचारिक रूप देता है (चार्ट XVI.4)।

स्तर I: उच्च सामरिक तात्कालिकता वाली गंभीर संवेदनशीलताएँ

16.33. इस स्तर में वे वस्तुएँ, घटक और प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं जिन तक पहुँच से वंचित किए जाने पर तत्काल और असममित राष्ट्रीय लागतें पड़ेंगी, तथा जिनकी वैश्विक आपूर्ति अत्यधिक संकेंद्रित है। इसके सामान्य उदाहरणों में रक्षा-महत्वपूर्ण प्रणालियाँ, मुख्य अवसंरचना इनपुट, ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े घटक, सार्वजनिक स्वास्थ्य की अनिवार्य वस्तुएँ और मौलिक औद्योगिक प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं।

16.34. स्तर I वस्तुओं के लिए उद्देश्य तनावपूर्ण परिस्थितियों में सुनिश्चित उपलब्धता है, न कि अल्पकालिक दक्षता। घरेलू उत्पादन उचित ठहराया जा सकता है, भले ही प्रारंभ में वह महँगा हो। हालांकि, समर्थन अनुशासित रहना चाहिए। लक्ष्य यह है कि परिभाषित समयावधि के भीतर न्यूनतम सुनिश्चित घरेलू क्षमता स्थापित की जाए, न कि स्थायी संरक्षण प्रदान किया जाए।

स्तर II: सामरिक फायदों के साथ आर्थिक रूप से फायदेमंद क्षमताएँ

16.35 इस स्तर में वे वस्तुएँ शामिल हैं जिनका घरेलू उत्पादन उचित लागत पर आर्थिक रूप से संभव है, किंतु समन्वय विफलताओं, ऐतिहासिक पथ-निर्भरता, प्रारंभिक पैमाने की कमी, या जमी हुई खरीद एवं अनुबंध प्रथाओं के कारण आयात जारी रहता है—न कि किसी वास्तविक तुलनात्मक अलाभ के कारण।

16.36. इस स्तर में स्वदेशीकरण मुख्यतः आर्थिक आधारों पर उचित ठहराया जाता है, जबकि सामरिक लाभ पूरक के रूप में कार्य करते हैं। उद्देश्य केवल संरक्षण प्रदान करना नहीं है, बल्कि पैमाने, अनुभव से सीखने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण के माध्यम से क्षमता निर्माण को तेज करना है। अस्थायी और लक्षित समर्थन कंपनियों को प्रारंभिक बाधाओं को पार करने में मदद कर सकता है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से समय-सीमित, प्रदर्शन-आधारित और उत्पादकता सुधार, लागत अभिसरण तथा निर्यात तत्परता पर निर्भर होना चाहिए। व्यवहार में, इस स्तर में वे विनिर्माण गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं जिनकी विशेषता मॉड्यूलर उत्पादन, पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं की संभावना, और प्रतिस्पर्धी निर्यात बाजारों के प्रति खुलापन है।

16.37. यदि निर्यात के प्रति खुलापन और विश्वसनीय निकास न हो, तो इस स्तर में किया गया हस्तक्षेप क्षमता निर्माण के बजाय अक्षमता को जड़ जमाने का जोखिम पैदा कर सकता है।

स्तर III: कम सामरिक तात्कालिकता या उच्च लागत वाला प्रतिस्थापन

16.38. इस स्तर में वे वस्तुएँ शामिल हैं जिनके लिए आयात पर निर्भरता किसी प्रणालीगत संवेदनशीलता को जन्म नहीं देती, जहाँ वैश्विक आपूर्ति विविधीकृत है या जहाँ घरेलू प्रतिस्थापन से मिलने वाले सामरिक लाभों की तुलना में अर्थव्यवस्था-व्यापी लागत अत्यधिक होगी।

16.39. इन वस्तुओं के लिए स्वदेशीकरण आवश्यक नहीं हो सकता है। जोखिम का बेहतर प्रबंधन घरेलू उत्पादन के बजाय विविधीकृत स्रोतों, भंडार बफरों या अनुबंधीय सुरक्षा उपायों के माध्यम से किया जा सकता है। ऐसे इनपुटों को स्वदेशी बनाने का प्रयास निचले स्तर की लागत बढ़ाने, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को कमजोर करने और लचीलापन नीति को विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र पर अप्रत्यक्ष कराधान में बदल देने का जोखिम पैदा करता है। ऐसी स्थितियों में, संयम स्वयं में सामरिक अनुशासन का एक रूप होता है।

चार्ट XVI.4 आयात प्रतिस्थापन से रणनीतिक लचीलेपन तक: रणनीतिक स्वदेशीकरण के लिए एक स्तरीय ढांचा

स्वदेशीकरण - उच्च तात्कालिकता वाले क्षेत्र		
	उच्च व्यवहार्यता ***निकट अवधि में क्षमता निर्माण यथार्थवादी*** ***स्तर 1 (अ-परक्राम्य)***	***निम्न-मध्यम व्यवहार्यता*** ***चरणबद्ध, दीर्घकालिक प्रयास आवश्यक*** ***स्तर 1 (सामरिक कोर)***
उच्च तात्कालिकता (मैक्रो/सुरक्षा जोखिम महत्वपूर्ण है)	• ***उद्देश्य:*** घरेलू उत्पादन क्षमता का तीव्र विस्तार • ***नीतिगत रुख:*** सुनिश्चित माँग, खरीद में प्राथमिकता, मानकों का संरेखण, समय-सीमित समर्थन • ***उत्पाद:*** खाद्य तेल व दालें, उर्वरक इनपुट, एपीआई, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक रसायन, दूरसंचार उपकरण	• ***उद्देश्य:*** पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं, बल्कि संवेदनशीलता में कमी • ***नीतिगत रुख:*** विविधीकरण, साझेदारियाँ, चयनात्मक री-शोरिंग, लर्निंग कर्व • ***उत्पाद:*** मैग्नेट, बैटरी सेल व कैथोड, सोलर वेफर व सेल
स्वदेशीकरण - विकासात्मक / क्षमता-निर्माण क्षेत्र		
	उच्च व्यवहार्यता ***निकट अवधि में क्षमता निर्माण यथार्थवादी*** **स्तर 2 (चयनात्मक गहनता)**	***निम्न-मध्यम व्यवहार्यता*** ***चरणबद्ध, दीर्घकालिक प्रयास आवश्यक*** **स्तर 2/3 (दीर्घकालिक क्षमता)**
निम्न-मध्यम तात्कालिकता (जोखिम प्रबंधनीय; विकास लक्ष्य प्रमुख) उच्च व्यवहार्यता निकट अवधि में क्षमता निर्माण संभव	• ***उद्देश्य:*** प्रतिस्पर्धात्मकता का उन्नयन • ***नीतिगत रुख:*** क्रमिक स्थानीयकरण, क्लस्टर, निर्यात, फर्म-स्तरीय सीख • ***उत्पाद:*** क्रेन्स, औद्योगिक मशीनरी, ईवी ड्राइवट्रेन, गैर-महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण	• ***उद्देश्य:*** पारिस्थितिकी तंत्र और कौशल/प्रतिभा निर्माण • ***नीति:*** सह-अभियांत्रिकी, टेस्ट-बेड, खरीद-आधारित सीख; निकट-कालिक स्थानीयकरण अनिवार्य नहीं • ***उत्पाद:*** टीबीएमएस, रेल सिग्नलिंग, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोलाइजर

16.40. ये स्तर स्थिर नहीं होते। जैसे-जैसे प्रौद्योगिकियाँ परिपक्व होती हैं, लागत घटती है, या भू-राजनीतिक परिस्थितियाँ बदलती हैं, वस्तुएँ एक स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरित हो सकती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि स्वदेशीकरण समकालिक नहीं, बल्कि क्रमिक रूप से आगे बढ़े और नीतिगत प्रयास उन क्षेत्रों पर केंद्रित हों जहाँ सामरिक प्रतिफल सर्वाधिक हों। जहाँ संभव हो, स्वदेशीकरण का अंतिम लक्ष्य निर्यात क्षमता बनना चाहिए—यही बुद्धिमान आयात प्रतिस्थापन की पहचान है।

एक नई राष्ट्रीय इनपुट लागत न्यूनीकरण रणनीति : अवसंरचना के रूप में प्रतिस्पर्धात्मकता

16.41. भारत के हित में निर्यात अनुशासन के प्रभावी रूप से काम करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्य और वहनीय हो। यदि लचीलेपन की रणनीतियाँ समूची अर्थव्यवस्था में लागत बढ़ा देती हैं, तो वे विफल भी हो सकती हैं। सफल औद्योगीकरण करने वाले देशों से बार-बार यह सीख मिलती है कि यदि अंतिम उत्पादों को तो संरक्षण दिया जाए, लेकिन इनपुट लागतें ऊँची बनी रहें, तो उत्पादन का विस्तार करना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो जाता है। वहनीय और भरोसेमंद इनपुट प्रतिस्पर्धात्मकता की आधारशिला हैं। भारत के संदर्भ में, यदि स्वदेशीकरण को इस प्रकार आगे बढ़ाना है कि वह निर्यात क्षमता को क्षीण किए बिना लचीलापन सुदृढ़ करे, तो उसे अनिवार्य रूप से इनपुट लागतों में प्रणालीगत कमी के साथ जोड़ा जाना चाहिए। यही एक राष्ट्रीय इनपुट लागत न्यूनीकरण रणनीति का तर्क और औचित्य है।

16.42 कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुओं, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स तथा अनुपालन से जुड़ी इनपुट लागतें विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मकता को आकार देती हैं। अंतिम उत्पादों के संरक्षण के विपरीत–जो सीमित संख्या में उत्पादकों को लाभ पहुँचाता है– उच्च इनपुट लागतें डाउनस्ट्रीम विनिर्माण, निर्यात और रोजगार पर व्यापक तथा स्थायी दंड के रूप में प्रभाव डालती हैं। निर्यात-उन्मुख विनिर्माण में कम लाभांश, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की उच्च संवेदनशीलता, और उन्नयन में निवेश करने के कमजोर प्रोत्साहन इस बाधा को और अधिक बाध्यकारी बना देते हैं। इस अर्थ में, इनपुट लागतें अवसंरचना की तरह कार्य करती हैं, क्योंकि वे पूरी अर्थव्यवस्था में लेन-देन लागतों को बढ़ा सकती हैं।

16.43 शुल्क उलटाव (टैरिफ इन्वर्जन) इस समस्या को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। जब मध्यवर्ती वस्तुओं पर आयात शुल्क अंतिम उत्पादों की तुलना में अधिक होते हैं, तो इससे डाउनस्ट्रीम उत्पादकों पर दंडात्मक प्रभाव पड़ता है और गहन घरेलू मूल्य संवर्धन के बजाय असेंबली-उन्मुख आयात को प्रोत्साहन मिलता है। इससे प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर होती है, निर्यात हतोत्साहित होते हैं और अंतिम उत्पादों के लिए संरक्षण पर निर्भरता बढ़ जाती है।

इस प्रकार की विकृतियों को सुधारना कोई सीमांत व्यापार समायोजन नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था-व्यापी प्रभावों वाला एक संरचनात्मक सुधार है।

16.44. इनपुट-लागत रणनीति का मूल तर्क क्षेत्र-विशिष्ट होने के बजाय नियम-आधारित है। ऐसे इनपुट जो विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं, उन्हें घरेलू क्षमता विकसित हो जाने के बाद न तो राजस्व के स्रोत के रूप में और न ही संरक्षण के उपकरण के रूप में देखा जाना चाहिए। ऐसे इनपुट को संरक्षण देने से कुछ सीमित उत्पादकों को लाभ हो सकता है, लेकिन इससे अनेक डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं की लागत बढ़ जाती है, जिससे प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार सृजन कमजोर पड़ता है। इनपुट लागतों में कमी एक साथ अनेक मूल्य शृंखलाओं को सुदृढ़ करती है।

16.45 एक सुव्यवस्थित, नियम-आधारित विकृति लेखा परीक्षण सुधारों का मार्गदर्शन कर सकता है और तदर्थ समायोजनों से बचा सकता है। इसके तहत यह प्रश्न पूछे जाने चाहिए कि क्या कोई इनपुट व्यापक

रूप से उपयोग में लाया जाता है, क्या उसकी घरेलू क्षमता मौजूद है, क्या संरक्षण से डाउनस्ट्रीम लागतें वास्तविक रूप से बढ़ती हैं और क्या निरंतर समर्थन किसी सामरिक उद्देश्य की पूर्ति करता है या केवल जमे हुए हितों को बनाए रखता है। जो इनपुट बिना किसी स्पष्ट औचित्य के अर्थव्यवस्था–व्यापी उच्च लागतें थोपते हैं, वे युक्तिकरण (रैशनलाइजेशन) के उपयुक्त उम्मीदवार बन जाते हैं।

16.46. जब स्वदेशीकरण और इनपुट–लागत न्यूनीकरण के दायरे स्पष्ट हों, तब दोनों एक–दूसरे के साथ सहअस्तित्व में रह सकते हैं। महत्त्वपूर्ण घटकों के लिए लक्षित समर्थन, क्षमता विकसित हो जाने के बाद सामान्य–उपयोग वाले इनपुटों पर प्रतिस्पर्धात्मक दबाव के साथ सहअस्तित्व रख सकता है। इससे स्वदेशीकरण को सर्वव्यापी संरक्षण में बदलने से रोका जा सकता है।

16.47. निस्संदेह, ऐसे सुधार कठिन होते हैं, क्योंकि इनके लाभ व्यापक रूप से बिखरे होते हैं, जबकि विरोध केंद्रित और संगठित रहता है। सुधारों को टिकाऊ बनाए रखने के लिए अर्थव्यवस्था–व्यापी लाभों का स्पष्ट प्रतिपादन तथा ऐसे नियम–आधारित प्रक्रियाएँ आवश्यक हैं, जो विवेकाधिकार और स्वार्थी कब्जे को सीमित करें । इनपुट लागतों में कमी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाती हैं, वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकरण को सुगम बनाती हैं, रोजगार में वृद्धि करती हैं और उन्नयन में निवेश करने के प्रोत्साहनों को सुदृढ़ करती हैं। सामरिक रूप से अपनाए जाने पर, ये विनिर्माण और निर्यात को एक–दूसरे को मजबूत करने की अनुमति देती हैं, जिससे लचीलापन और बाहरी स्थिरता दोनों सुदृढ़ होते हैं।

16.48. इनपुट लागतों को कम करना प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए एक आवश्यक आधार है, लेकिन क्षमता निर्माण के लिए यह पर्याप्त नहीं है। कम लागतें प्रणाली–व्यापी बाधाओं को दूर करती हैं, परंतु वे स्वयं अनुशासन, सीखने की प्रक्रिया या पैमाने का निर्माण नहीं करतीं। जैसे ही अर्थव्यवस्था लागत–प्रतिस्पर्धी बन जाती है, तो बाध्यकारी सीमा कीमतों से हटकर प्रदर्शन पर आ जाती है—जिसका स्वरूप विश्वसनीयता, प्रक्रिया नियंत्रण, गुणवत्ता तथा संस्थानों के बीच समन्वय के रूप में सामने आता है। इसी चरण पर उन्नत विनिर्माण निर्णायक बन जाता है। उन्नत विनिर्माण उन कमजोरियों को उजागर करता है जिन्हें संरक्षित गतिविधियाँ लंबे समय तक सहन कर सकती हैं। यह अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स, विनियमन, कौशल और प्रवर्तन—सभी की एक साथ परीक्षा लेता है और वह भी ऐसे बाहरी मानकों के अंतर्गत जिन्हें बातचीत या समझौते से हटाया नहीं जा सकता। इस अर्थ में, इनपुट–लागत न्यूनीकरण भूमि को तैयार करता है, लेकिन वास्तविक क्षमता का निर्माण और प्रकटीकरण उन्नत विनिर्माण के स्तर पर ही होता है।

उन्नत विनिर्माण एक अनुशासनात्मक प्रणाली के रूप में : क्यों विनिर्माण संस्थानों को आकार देता है

16.49. उन्नत विनिर्माण केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वह उत्पादन और निर्यात का विस्तार करता है, बल्कि इसलिए भी कि वह उन कमजोरियों को उजागर करता है जिन्हें संरक्षित गतिविधियाँ लंबे समय तक ढो सकती हैं। जब उत्पादन प्रक्रिया–आधारित, पैमाना–सघन और वैश्विक मानकों के अनुरूप तुलनात्मक होता है, तब छोटी–छोटी बाधाएँ भी लागत, गुणवत्ता और विश्वसनीयता में विफलताओं के रूप में संचयी प्रभाव डालती हैं। इसी कारण उन्नत विनिर्माण राज्य और फर्म के लिए एक तनाव–परीक्षण बन जाता है। यह पूर्वानुमेय नियमों, भरोसेमंद अवसंरचना, तेज लॉजिस्टिक्स, प्रवर्तनीय अनुबंधों और संस्थागत

अनुवर्तन को अनिवार्य बनाता है। लागत नियंत्रण, परिचालन विश्वसनीयता और सतत सुधार अस्तित्व की शर्तें बन जाते हैं, न कि वैकल्पिक आकांक्षाएँ। समायोजन असहज हो सकता है, किंतु वह रूपांतरणकारी भी होता है।

16.50. उन गतिविधियों के विपरीत जो पृथक क्षेत्रों (एन्क्लेव) में संचालित हो सकती हैं, विनिर्माण आपूर्ति शृंखलाओं और कारक बाजारों में गहराई से अंतर्निहित होता है। यह बंदरगाहों, विद्युत गुणवत्ता, परिवहन की विश्वसनीयता, मानकों और प्रमाणीकरण, विवाद निपटान तथा पूर्वानुमेय प्रशासन पर निर्भर करता है। जब ये कमजोर होते हैं, तो उसका दंड तत्काल और बाह्य रूप से स्पष्ट दिखाई देता है। इस अर्थ में, विनिर्माण केवल राज्य क्षमता से लाभान्वित नहीं होता; यह उसे सक्रिय रूप से सामने भी लाता है, क्योंकि शासन की विफलताओं को छिपाना महँगा हो जाता है।

16.51 संरक्षित गतिविधियों और संरक्षित क्षेत्रों में, फर्म दक्षता के स्थान पर पहुँच का सहारा लेकर भी जीवित रह सकते हैं। विनियामक विवेकाधिकार, प्रशासनिक मध्यस्थता या संरक्षण–उत्पादकता पिछड़ने के बावजूद–लाभप्रदता को बनाए रख सकते हैं। इसके विपरीत, उन्नत विनिर्माण में अस्तित्व पूरी तरह क्रियान्वयन पर निर्भर करता है, न कि मोलभाव पर; और यही दबाव फर्मो, संस्थानों तथा प्रोत्साहनों को पुनर्गठित कर देता है।

सीखना, पैमाना और प्रतिस्पर्धा का अनुशासन

16.52 विनिर्माण क्षमता संचय के माध्यम से बनती है, घोषणा से नहीं। प्रारंभिक चरण प्रायः अलाभकारी होते हैं और सीख दोहराए गए प्रक्रिया सुधार, आपूर्तिकर्ता विकास तथा क्रमिक उन्नयन के माध्यम से होती है। किंतु सीख तभी क्षमता में रूपांतरित होती है जब वह अनुशासन के साथ जुड़ी हो। जो समर्थन बिना शर्त और स्थायी होता है, वह संरक्षण बन जाता है। इसके विपरीत, जो समर्थन समयबद्ध और प्रदर्शन–आधारित होता है, वह सीख को सक्षम बनाते हुए प्रतिस्पर्धात्मकता को भी प्रोत्साहित कर सकता है–विशेष रूप से निर्यात के माध्यम से मिलने वाले बाह्य दबाव के जरिये।

16.53. भारत का अनुभव सेवाओं-आधारित विकास के साथ एक स्पष्ट विरोधाभास भी उजागर करता है। सेवा निर्यातक अक्सर विशेषीकृत अवसंरचना, नियामकीय अपवादों (रेगुलेटरी कार्व–आउट्स) या घरेलू आपूर्ति शृंखलाओं से संगठनात्मक पृथक्करण के माध्यम से काम कर सकते हैं। परिणामस्वरूप, व्यापक लेन–देन लागतें ऊँची बनी रहने पर भी सेवाएँ फल–फूल सकती हैं। इसके विपरीत, विनिर्माण एक साथ अनेक कारक बाजारों और सार्वजनिक प्रणालियों को सक्रिय करता है। लॉजिस्टिक्स, मानक प्रवर्तन या समन्वय में मौजूद कमजोरियाँ शीघ्र और स्पष्ट रूप से सामने आ जाती हैं।

पूर्वी एशिया क्यों महत्वपूर्ण है (और क्यों इसे अक्सर गलत समझा जाता है)

16.54. स्वदेशीकरण, आयात प्रतिस्थापन या औद्योगिक नीति की किसी भी चर्चा में अनिवार्य रूप से पूर्वी एशिया का उल्लेख आता है। जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, चीन और हाल ही में वियतनाम को सफलता की कहानियों के रूप में नियमित रूप से उद्धृत किया जाता है। फिर भी, इन अनुभवों से ली गई सीखें अक्सर सतही या चयनात्मक होती हैं। कुछ पर्यवेक्षक केवल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं,

जबकि अन्य निर्यात उन्मुखीकरण या मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता पर जोर देते हैं। दोनों ही उस गहन संस्थागत तर्क को नजरअंदाज कर देते हैं जिसने इन रणनीतियों को सफल बनाया। पूर्वी एशिया से मिलने वाली केंद्रीय सीख यह नहीं है कि राज्य ने हस्तक्षेप किया, बल्कि यह है कि उसने कैसे हस्तक्षेप किया–और उतना ही महत्वपूर्ण, कैसे बाहर निकला। ये अर्थव्यवस्थाएँ इसलिए सफल हुई कि उन्होंने गलतियों से सीखने और जब दांव असफल हुए तो संसाधनों को पुनः आवंटित करने के लिए अपने सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया था। इसके लिए एक स्तर की नियामकीय स्वायत्तता, राजनीतिक समर्थन और प्रदर्शन अनुशासन आवश्यक था, जिसे कई देशों के लिए बनाए रखना कठिन था।

16.55. भारत के लिए, पूर्वी एशिया का उदाहरण इस बात को समझाने के लिए दिया गया है कि पूर्वी एशिया के औद्योगिकीकरण के पीछे प्रभावी सरकारी मशीनरी का आधार है । उस संरचना के बिना, समान दिखने वाली नीतियाँ बिल्कुल भिन्न परिणाम दे सकती हैं।

बॉक्स XVI.1: पूर्वी एशिया – राज्य क्षमता की संरचना

जापान : परिणामों पर आधारित नौकरशाही अधिकार

जापान का युद्धोत्तर औद्योगिकीकरण अक्सर इसकी शक्तिशाली आर्थिक नौकरशाही, विशेषकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार और उद्योग मंत्रालय (MITI) से जुड़ा हुआ माना जाता है। जो बात कम समझी जाती है, वह यह है कि जापानी नौकरशाह किन प्रोत्साहन संरचनाओं के तहत काम करते थे।

अधिकारियों को मंत्रालयों में लंबी अवधि तक कार्य करने का अवसर मिलता था, उन्हें गहन क्षेत्रीय विशेषज्ञता प्राप्त थी और नीति निर्माण में पर्याप्त विवेकाधिकार प्राप्त था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी करियर यात्रा किसी एक परियोजना की विफलता से बाधित नहीं होती थी, बशर्ते वह परियोजना राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप हो और अच्छी नीयत के साथ लागू की गई हो। इससे प्रयोग करने का डर कम होता था और योजनाबद्ध जोखिम लेने को प्रोत्साहन मिलता था।

साथ ही, फर्मों को दिया जाने वाला समर्थन कभी भी बिना शर्त नहीं था। अनुदान, क्रेडिट पहुँच और संरक्षण प्रदर्शन संकेतकों से जुड़ा होता था, जिनमें निर्यात वृद्धि, तकनीकी उन्नयन और पैमाना शामिल थे। जब फर्में अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरती थीं, तो समर्थन वापस ले लिया जाता था, भले ही इससे अल्पकालिक व्यवधान उत्पन्न हो।

जापानी मॉडल ने नौकरशाही सशक्तीकरण को परिणामों की जवाबदेही के साथ जोड़ा, न कि प्रक्रियाओं की। यह राज्य और उद्योग के बीच घने सूचना प्रवाह पर भी निर्भर करता था, जिससे नीति-निर्माताओं को स्थिर योजनाओं के बजाय वास्तविक दुनिया की प्रतिक्रिया के आधार पर रणनीतियों को अद्यतन करने की अनुमति मिलती थी।

दक्षिण कोरिया : असफलताओं की सहनशीलता और कट्टरतापूर्वक समर्थन समाप्ति

दक्षिण कोरिया का अनुभव शायद अनुशासित औद्योगिक नीति का सबसे स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। कोरियाई राज्य ने राष्ट्रीय चौंपियनों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया, निर्देशित क्रेडिट उपलब्ध कराया और शुरुआती चरणों में घरेलू बाजारों की रक्षा की। फिर भी, यह समर्थन स्पष्ट अपेक्षाओं और अप्रदर्शन के गंभीर परिणामों के साथ आया।

नौकरशाह अक्सर सरकार और उद्योग के बीच घूर्णन करते थे, जिससे उत्पादन संबंधी बाधाओं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की व्यावहारिक समझ सुनिश्चित होती थी। यदि असफलता राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप थी, तो यह करियर समाप्त नहीं करती थी। जो स्वीकार्य नहीं था, वह था लगातार और स्थायी रूप से कमजोर प्रदर्शन।

जब फर्में निर्यात लक्ष्यों को पूरा करने या तकनीकी उन्नयन हासिल करने में विफल होती थीं, तो राज्य समर्थन वापस ले लेता था। कई चौबोल राज्य के दबाव में ढह गए या पुनर्गठित किए गए। इस प्रणाली की राजनीतिक–आर्थिक संरचना कठोर थी, लेकिन इसने उन "जॉम्बी" फर्मों के जमाव को रोका जो केवल संरक्षण पर जीवित रहतीं।

भारत के लिए, कोरियाई सबक यह है कि अनुशासन दिखाई देने योग्य, पूर्वानुमेय और लागू किया जाने वाला होना चाहिए, भले ही यह राजनीतिक रूप से असुविधाजनक क्यों न हो।

सिंगापुर: गति, नियामक लचीलापन और विश्वसनीयता

सिंगापुर एक विपरीत लेकिन पूरक मॉडल प्रस्तुत करता है। बड़े घरेलू बाजार की कमी के कारण उसने वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में अपरिहार्य बनने पर ध्यान केंद्रित किया—विश्वसनीयता, गति और नियामक विश्वसनीयता के माध्यम से।

नियामक एजेंसियों को निवेश और नवाचार को सुगम बनाने के लिए नियमों को अस्थायी रूप से माफ करने या अनुकूलित करने का अधिकार दिया गया। औपचारिक पूर्णता की तुलना में क्रियान्वयन की गति को अधिक महत्व दिया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस लचीलेपन के साथ–साथ, एक बार मानक तय हो जाने पर सख्‌त प्रवर्तन भी किया गया, जिससे विश्वास और पूर्वानुमेयता बनी रही।

सिंगापुर का अनुभव उस आयाम को उजागर करता है जिसे भारतीय बहसों में अक्सर नजरअंदाज किया जाता है: नियामक घर्षण स्वयं एक प्रतिस्पर्धात्मकता का चर है। अच्छी तरह से डिजाइन की गई औद्योगिक नीतियाँ भी विफल हो सकती हैं यदि अनुमोदन, स्वीकृतियाँ और विवाद समाधान धीमे या अनिश्चित हों।

वियतनाम: लगातार लागत न्यूनीकरण और संस्थागत सीख

वियतनाम की हाल की विनिर्माण सफलता इस बात को रेखांकित करती है कि निरंतर लागत में कमी और संस्थागत अनुकूलन कितने महत्वपूर्ण हैं। संरक्षण पर अत्यधिक निर्भर रहने के बजाय, वियतनाम ने नियामक और लेन–देन लागतों को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया—कुछ अवधियों में यह कमी लगभग 20 प्रतिशत तक बताई जाती है।

इस दृष्टिकोण ने वियतनाम को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना दिया, विशेषकर उन कंपनियों के लिए जो विविधीकरण चाहती थीं। यद्यपि उसका घरेलू तकनीकी आधार अभी भी सीमित है, लेकिन वैश्विक विनिर्माण नेटवर्क में उसका एकीकरण सीखने और क्षमता निर्माण को तेज कर रहा है।

यहाँ सबक यह है कि संरक्षण अनावश्यक नहीं है, लेकिन प्रतिस्पर्धात्मकता बहुआयामी होती है। लागत संरचनाएँ, नियामक दक्षता और श्रम उत्पादकता उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि शुल्क नीति।

साझा सूत्र : उद्यमशील राज्य (कॉमन थ्रेड : एंटरप्रेन्योरियल स्टेट)

16.56. भले ही पूर्वी एशियाई अनुभवों में अंतर हो, फिर भी उनमें एक साझा संस्थागत तर्क मौजूद है, अर्थात् एक उद्यमशील राज्य की उपस्थिति। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य बाजारों की जगह ले, बल्कि ऐसा राज्य जो प्रयोग करने, योजनाबद्ध जोखिम लेने, असफलताओं को आत्मसात करने और समर्थन को गतिशील रूप से पुनः आवंटित करने के लिए तैयार हो। यह दृष्टिकोण विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है जब नीति अनिश्चितता के तहत बनाई जाती है, परिणाम पहले से ज्ञात नहीं होते और गलतियों को हमेशा बिना लागत के उलटा नहीं किया जा सकता।

16.57. तीन विशेषताएँ स्पष्ट रूप से सामने आती हैं :

i. परिणाम-उन्मुख नौकरशाही: अधिकारियों का मूल्यांकन नियमों के पालन पर नहीं, बल्कि परिणामों पर किया जाता है।

ii. विफलता सहनशीलता और सीख : त्रुटियाँ स्वीकार्य हैं; ठहराव नहीं।

iii. विश्वसनीय समर्थन वापसी : प्रवेश जितना महत्वपूर्ण है, निकास भी उतना ही।

16.58. ये विशेषताएँ उन प्रणालियों में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं जहाँ औद्योगिक नीति असफल रही है। जहाँ ईमानदार असफलता के लिए नौकरशाही को दंडित किया जाता है, वहाँ जोखिम से बचाव हावी हो जाता है। जहाँ समर्थन वापस नहीं लिया जा सकता, वहाँ अकुशलता जड़ पकड़ लेती है। ऐसी प्रणालियों में, संस्थाएँ अनिश्चितता के प्रति सीखने और अनुकूलन के बजाय कुल मिलाकर कार्रवाई से बचती हैं, जिससे समय के साथ राज्य क्षमता कमजोर होती जाती है।

16.59. पूर्वी एशियाई अनुभव भारत के लिए कोई तैयार-निर्मित फॉर्मूला पेश नहीं करता। लेकिन यह स्पष्ट संदेश देता है कि संस्थागत सुधार के साथ औद्योगिक नीति के सफल होने की संभावना कहीं अधिक होती है। यह लचीलेपन और प्रभाव के बीच का अंतर एशिया में आर्थिक शक्ति के बाह्य तुलनात्मक आकलनों में भी परिलक्षित होता है, जैसा कि बॉक्स XVI.2 में चर्चा की गई है।

बॉक्स XVI.2: लचीलेपन से प्रभाव तक – एशिया में भारत का शक्ति अंतर

हालिया बाहरी आकलन लचीलेपन और प्रभाव के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हैं। इस संदर्भ में, लोवी इंस्टिट्यूट का एशिया पावर इंडेक्स (2025)[8] एक उपयोगी दृष्टिकोण प्रदान करता है।

इस इंडेक्स में संसाधनों (देश के पास क्या है) और प्रभाव (ये संसाधन क्षेत्रीय परिणामों में कितनी प्रभावी ढंग से परिवर्तित हो रहे हैं) के बीच अंतर किया गया है। इसके साथ ही पावर गैप की अवधारणा पेश की गई है, जो एक देश की अपेक्षित प्रभावशीलता (संसाधनों के आधार पर) और वास्तविक प्रभावशीलता के बीच के अंतर को मापती है।

भारत की प्रोफाइल इस सूचकांक में शिक्षाप्रद है। भारत अब एशिया में प्रमुख शक्ति का दर्जा प्राप्त कर चुका है और उसकी समग्र शक्ति लगातार बढ़ रही है। 2018 में सूचकांक की शुरुआत के बाद पहली बार भारत की आर्थिक संबंधों पर रैंकिंग में सुधार हुआ है। उल्लेखनीय रूप से, भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए

8 लोवी इंस्टिट्यूट। एशिया पावर इंडेक्स। 2025 संस्करण। https://power.lowyinstitute.org/power-gap/

एशिया में (संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद) सबसे बड़ा आंतरिक निवेश गंतव्य बन गया है, जिसे दस-वर्षीय संचयी आधार पर मापा गया है। यह आपूर्ति श्रृंखलाओं के भू-राजनीतिक विविधीकरण और निवेश गंतव्य के रूप में भारत की बढ़ती आकर्षण को दर्शाता है।

साथ ही, सूचकांक लगातार अंतरालों को भी उजागर करता है। भारत समग्र शक्ति में तीसरे स्थान पर है, लेकिन आर्थिक संबंधों में दसवें स्थान पर है और – 4.0 का नकारात्मक 'पावर गैप' दर्ज करता है, जो यह संकेत देता है कि भारत अभी तक अपने संसाधनों को बाहरी आर्थिक प्रभाव में परिवर्तित नहीं कर पा रहा है।

जो तस्वीर उभरती है वह मिश्रित लेकिन खुलासा करने वाली है। भारत ने वैश्विक झटकों के सामने मजबूत लचीलापन और अवशोषण क्षमता प्रदर्शित की है। उसके विकास की अगली चुनौती अलग है: केवल स्थिरता का प्राप्तकर्ता बनने से आगे बढ़कर दूसरों के लिए स्थिरता और अवसर का स्रोत बनना।

यह लचीलेपन से परस्पर निर्भरता की ओर संक्रमण भारत की षविकसित भारतष यात्रा का केंद्रीय हिस्सा है। यह इस बात को रेखांकित करता है कि प्रतिस्पर्धात्मकता, निर्यात क्षमता और क्षेत्रीय एवं वैश्विक उत्पादन नेटवर्क में गहरी एकीकृत भागीदारी, एक खंडित विश्व में प्रभावशाली बनने के आवश्यक साधन हैं।

स्वदेशी से सामरिक लचीलेपन से सामरिक अपरिहार्यता तक

16.60. भारत की नीतिगत चुनौती केवल आयात प्रतिस्थापन या स्वदेशीकरण या घरेलू औद्योगिक नीति को संस्थागत सुधारों के माध्यम से लागू करने तक सीमित नहीं है और इसे इस प्रकार बुद्धिमानी से करना कि उद्योग विश्व मानकों को पूरा कर सके। भारत को उन क्षेत्रों में घरेलू क्षमता भी विकसित करनी होगी जो उसे सामरिक रूप से लचीला बना सकें। सामरिक लचीलेपन का अर्थ है बाहरी झटकों का सामना करने के लिए बफर और ताकतों का निर्माण करना। इसका मतलब है राष्ट्रीय शक्ति में निवेश करना। बुद्धिमान आयात प्रतिस्थापन राष्ट्रीय शक्ति में निवेश का पहला कदम है। 'राष्ट्रीय शक्ति में निवेश' हमें अगले चरण 'सामरिक लचीलेपन' तक ले जाता है और फिर अंतिम चरण 'सामरिक अपरिहार्यता' तक। तालिका XVI.1 इस भेद को औपचारिक रूप देती है, जिसमें आयात प्रतिस्थापन, सामरिक लचीलेपन और सामरिक अपरिहार्यता को उनके मूल उद्देश्य के संदर्भ में साथ-साथ रखा गया है।

तालिका XVI.1: प्रस्तावित वैचारिक परिभाषाएँ

अवधारणा	परिभाषा	मुख्य उद्देश्य
आयात प्रतिस्थापन	एक ऐसी आर्थिक रणनीति जो उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करती है, जिन्हें पहले आयात किया जाता था।	पहले जो चीजें आयात होती थीं, उन्हें देश में ही बनाकर आयात पर निर्भरता कम करना।
सामरिक लचीलापन	किसी अर्थव्यवस्था या प्रणाली की वह व्यापक क्षमता, जिसके माध्यम से वह भू-राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी अथवा पर्यावरणीय सहित बाहरी झटकों को सहन कर सके और अपना कार्य संचालन जारी रख सके।	दबाव की परिस्थितियों में महत्वपूर्ण आपूर्ति शृंखलाओं और क्षमताओं की निरंतरता, अनुकूलनशीलता और सुरक्षा सुनिश्चित करना।

सामरिक अपरिहार्यता	अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रणालियों के साथ इस प्रकार एकीकृत करना कि वह वैश्विक व्यवस्था के लिए मूलतः महत्वपूर्ण बन जाए और अन्य पक्ष उसकी निरंतर कार्यशीलता में रुचि तथा निवेश करने लगें।	वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाना तथा भू-राजनीतिक वार्ताओं और संघर्षों में प्रभावी दबाव और सौदेबाजी की क्षमता प्राप्त करना।

16.61 तालिका XVI.2 यह दर्शाती है कि यह संक्रमण नीति के आर्थिक फोकस, समय क्षितिज और भौगोलिक तर्क को किस प्रकार बदल देता है। तालिका XVI.3 इसे पूरक रूप से आगे बढ़ाती है, जिसमें यह संक्षेप में बताया गया है कि इन चरणों के साथ आधारभूत मान्यताएँ, नीति उपस्कर और जोखिम उन्मुखता किस प्रकार विकसित होती जाती हैं।

तालिका XVI.2: आयात प्रतिस्थापन से सामरिक अपरिहार्यता तक – एक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य

आयाम	आयात प्रतिस्थापन	सामरिक लचीलापन	सामरिक अपरिहार्यता
आर्थिक फोकस	मुख्यतः क्षेत्र-आधारित (विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तुएँ, मध्यवर्ती वस्तुएँ)।	प्रणालीगत (ऊर्जा, खाद्य, डाटा, स्वास्थ्य, रक्षा, अवसंरचना और प्रौद्योगिकी जैसे अनेक क्षेत्रों में विस्तारित)।	राष्ट्रीय उद्योगों और प्रौद्योगिकियों को वैश्विक नेटवर्क में अपरिहार्य केंद्र बिंदुओं के रूप में एकीकृत करना।
समय क्षितिज	अल्प-से-मध्यम अवधि का औद्योगिक नीति उपकरण।	मध्यम-से-दीर्घ अवधि का राष्ट्रीय क्षमता ढाँचा।	वैश्विक मूल्य शृंखलाओं और संस्थानों में दीर्घकालिक संरचनात्मक स्थिति सुनिश्चित करना।
भौगोलिक तर्क	**घर पर ही उत्पादन करें :** घरेलू मूल्य संवर्धन पर ध्यान दें।	**विविधीकरण और सुरक्षा:** घरेलू, सहयोगी तथा मित्र देशों के स्रोतों का मिश्रण।	**आकार देना और आधार बनाना :** महत्वपूर्ण वैश्विक परस्पर-निर्भरताओं का निर्माण और नियंत्रण।

तालिका XVI-3: आयात प्रतिस्थापन, सामरिक लचीलेपन और सामरिक अपरिहार्यता में नीति तर्क और जोखिम उन्मुखता

	आयात प्रतिस्थापन	सामरिक लचीलापन	सामरिक अपरिहार्यता
मुख्य धारणा	घरेलू क्षमता आयातों की प्रभावी रूप से पूर्ति कर सकती है	वैश्विक परस्पर-निर्भरता बनी रहेगी; अतिरिक्तता और विविधीकरण के माध्यम से जोखिम प्रबंधन आवश्यक है।	वैश्विक परस्पर-निर्भरता को आकार दिया जा सकता है; राष्ट्रीय शक्ति इस बात में निहित है कि आपकी भूमिका ऐसी हो कि अन्य इसे बायपास न कर सकें।

नीति उपकरण	प्रशुल्क, स्थानीय सामग्री अनिवार्यता, अनुदान, संरक्षणात्मक उपाय।	सप्लाई चेन मानचित्रण, अतिरिक्तता योजना, मित्र राष्ट्र आधारित शोरिंग, भंडारण, द्विगुणित स्रोत, अनुसंधान एवं विकास सुरक्षा।	प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए क्षैतिज और पारिस्थितिकी तंत्र की दक्षताओं का निर्माण, वैश्विक प्रभुत्व का लक्ष्य।
जोखिम फोकस	व्यापार घाटा, औद्योगिक विकास में कमी।	प्रणालीगत कमजोरियाँ, जिनमें ऊर्जा झटके, महामारी, साइबर हमले और भू-राजनीतिक दबाव शामिल हैं।	वैश्विक प्रभाव या प्रासंगिकता, बाहरी नियम निर्माण या प्रौद्योगिकी पारिस्थितिक तंत्र के प्रति अति-निर्भरता।

16.62 भारत की चुनौती यह है कि आत्मनिर्भरता के तीन चरण, जो हमें विकसित भारत के लक्ष्य के करीब लाएँगे, आज की दुनिया में हो रहे तीव्र परिवर्तनों के कारण एक-दूसरे में समाहित हो गए हैं। व्लादिमीर इलिच लेनिन का प्रसिद्ध उद्धरण है: "ऐसे दशक होते हैं जब कुछ नहीं होता; और ऐसे सप्ताह होते हैं जब दशकों का घटनाक्रम घटित हो जाता है।" हम ऐसे समय में हैं जब दशकों की घटनाएँ सप्ताहों में घटित होती प्रतीत होती हैं। दिलचस्प बात यह है कि वर्तमान परिदृश्य में रूस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

16.63 इसलिए भारत को आयात प्रतिस्थापन, सामरिक लचीलेपन और सामरिक अपरिहार्यता जैसी अपनी निकट, मध्यम और दीर्घकालिक नीतिगत प्राथमिकताओं को एक साथ आगे बढ़ाना होगा। समय बर्बाद करने का अवसर नहीं है। यह ऐसा है जैसे एक ही समय में मैराथन और स्प्रिंट दौड़ना, या मैराथन को स्प्रिंट की तरह दौड़ना!

16.64 आत्मनिर्भर भारत को अक्सर आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों, भू-राजनीतिक तनावों या आर्थिक दबावों के प्रति एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। यद्यपि लचीलापन एक आवश्यक उद्देश्य है, यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। जो राष्ट्र केवल झटकों को सहता है, वह प्रतिक्रियाशील बना रहता है। जो राष्ट्र परिणामों को आकार देता है, वह प्रभावशाली बनता है। यह आत्मनिर्भरता से ऊँचा मानक है और लचीलेपन से अधिक चुनौतीपूर्ण आकांक्षा है।

16.65 आर्थिक शक्ति का सर्वोच्च रूप वह प्रभाव है जो बिना किसी दबाव के प्रयोग किया जाता है—जब अन्य देश हमारे हितों के साथ इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि यह उनके हित में भी है। सामरिक अपरिहार्यता ठीक इसी प्रकार की शक्ति प्रदान करती है। सामरिक अपरिहार्यता के साथ वैश्विक प्रभाव आता है। जब वैश्विक कंपनियाँ भारतीय उत्पादन पर निर्भर होती हैं, जब आपूर्ति श्रृंखलाओं को भारत के बिना आसानी से पुनर्गठित नहीं किया जा सकता, और जब भारतीय निर्यात पर स्वत: विश्वास किया जाता है, तब देश की आवाज अपनी सीमाओं से परे महत्व रखती है। यही है रणनीति पर आधारित आत्मनिर्भर भारत का वादा।

16.66 सरल शब्दों में, जब दुनिया "भारतीय वस्तुएँ खरीदने के बारे में सोचने" से "बिना सोचे भारतीय वस्तुएँ खरीदने" की ओर बढ़ेगी, तब भारत सामरिक अपरिहार्यता प्राप्त कर लेगा। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत को चुनौती दी थी कि स्वदेशी का अर्थ है—सबसे उच्च

गुणवत्ता वाले उत्पादों को सबसे कम संभव कीमत पर तैयार करना, ताकि लोग स्वतः भारतीय वस्तुएँ खरीदने की ओर आकर्षित हों।

विनिर्माण, निर्यात क्षमता और मुद्रा की मजबूती

16.67 स्वदेशी का मूल्यांकन केवल आयात में कमी से नहीं, बल्कि निर्यात क्षमता के निर्माण से किया जाना चाहिए। क्षमता निर्माण तत्काल और महत्वपूर्ण दोनों है, ऐसे समय में जब पूँजी प्रवाह अधिकतर भू-राजनीतिक संरेखण और राष्ट्रीय हितों द्वारा आकार ले रहे हैं, न कि तटस्थ बाजार बलों द्वारा। जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है, उसके आयात में वृद्धि होना अपेक्षित है। पिछली दो सदियों के आर्थिक विकास का इतिहास इस प्रवृत्ति की पुष्टि करता है, और इसलिए इसे नीति-विफलता नहीं माना जाना चाहिए। वास्तव में, आय में वृद्धि और अर्थव्यवस्थाओं के विविधीकरण के साथ आयात का बढ़ना अपरिहार्य ही नहीं, बल्कि वांछनीय भी होता है। चार्ट XVI.5 इसी पैटर्न को दर्शाता है, जिसमें दिखाया गया है कि जैसे-जैसे चीन की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, उसके आयात भी बढ़े—हालाँकि इसी अवधि में चीन इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, कारों और ड्रोन जैसी वस्तुओं का वैश्विक शीर्ष उत्पादक बन गया।

चार्ट XVI.5: चीन का आयात विकास और प्रति-व्यक्ति आय में वृद्धि

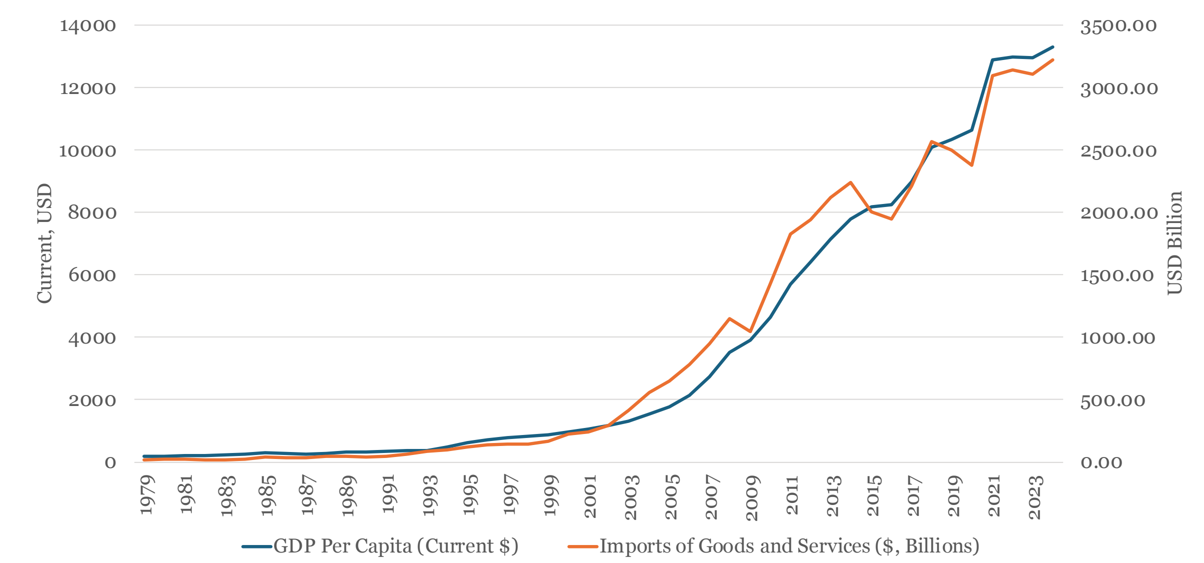

Source: World Bank Data

16.68 भारत के मामले में, ऐसी अपरिहार्य आयात वृद्धि मुद्रा की संवेदनशीलता को और अधिक स्पष्ट करती है। एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में, भारत के लिए एक मजबूत और स्थिर मुद्रा की आकांक्षा करना उचित है। मुद्रा की मजबूती अक्सर विकसित अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ी होती है। हालाँकि, "हार्ड करेंसी" की धारणा को अक्सर केवल मौद्रिक रूढ़िवादिता या केंद्रीय बैंक की विश्वसनीयता से प्रेरित माना जाता है। जबकि ये आवश्यक शर्तें हैं, वे अपने आप में पर्याप्त नहीं हैं।

16.69 विनिमय दर को नीति उद्देश्य के बजाय एक संकेत के रूप में समझना सबसे उपयुक्त है। यह व्यापार संतुलन, पूँजी प्रवाह, जोखिम धारणाओं और भू-राजनीति के संयोजन को दर्शाती है। हार्ड करेंसी का व्यवहार तब उभरता है जब बाजारों को विश्वास होता है कि कोई देश व्यापार के माध्यम से विश्वसनीय

रूप से विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकता है, कि बाहरी देनदारियाँ उत्पादक बाहरी परिसंपत्तियों से मेल खाती हैं, कि अर्थव्यवस्था आपातकालीन वित्तपोषण के बिना झटकों का सामना कर सकती है, और कि मुद्रा अवमूल्यन प्राथमिक समायोजन तंत्र नहीं है।

16.70 ऐतिहासिक रूप से, वे मुद्राएँ जिन्होंने ऐसा व्यवहार प्रदर्शित किया है—जर्मनी, जापान, स्विट्ज़रलैंड और बाद में पूर्वी एशियाई औद्योगीकरणकर्ताओं की—उनकी नींव पूँजी प्रवाह पर निर्भरता के बजाय निर्यात क्षमता पर टिकी रही है। मौद्रिक अनुशासन ने इस नींव को मजबूत किया; इसे बनाया नहीं। पूँजी प्रवाह विकास का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन वे उलटने योग्य होते हैं। इसके विपरीत, निर्यात आय प्रतिस्पध र्ात्मकता के माध्यम से बार-बार अर्जित की जाती है, केवल विश्वास के आधार पर नहीं। भारत की मुद्रा, इसके विपरीत, संरचनात्मक रूप से नरम बनी हुई है। यह नीति की विफलता नहीं है, बल्कि अंतर्निहित व्यापार गतिशीलता का प्रतिबिंब है। जब तक आर्थिक विकास यांत्रिक रूप से व्यापार घाटे को चौड़ा करता रहेगा, विनिमय दर को बाहरी दबाव के विरुद्ध बफर के रूप में कार्य करना जारी रखना होगा।

16.71 इसलिए, जब तक निर्यात क्षमताओं का तीव्र विकास नहीं होता, मुद्रा अवमूल्यन प्राथमिक समायोजन तंत्र बना रहेगा। यहाँ जिस निर्यात क्षमता की परिकल्पना की गई है, वह मुख्यत: विनिर्माण निर्यात से संबंधित है, न कि सेवा निर्यात से, जिसमें भारत ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। आईटी, व्यापार सेवाओं और पेशेवर सेवाओं में भारत का प्रदर्शन असाधारण रहा है। इन निर्यातों ने विदेशी मुद्रा अर्जित की है, विकास को समर्थन दिया है और वैश्विक एकीकरण को गहरा किया है। हालाँकि, सेवा निर्यातों की अंतर्निहित सीमाएँ हैं। वे बड़े पैमाने पर कम रोजगार-गहन होते हैं, कम पिछड़े संबंध उत्पन्न करते हैं, खुले डिजिटल ढाँचों पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं और भौतिक आपूर्ति श्रृंखलाओं को स्थिर नहीं करते। वे आवश्यक हैं, लेकिन औद्योगीकरण की आयात-गहनता को संतुलित करने के लिए पर्याप्त नहीं। इसके विपरीत, विनिर्माण निर्यात आपूर्तिकर्ता पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं, बड़े कार्यबल को समाहित करते हैं और जब पैमाने पर बढ़ते हैं तो टिकाऊ व्यापार अधिशेष उत्पन्न करते हैं। यही एकमात्र सिद्ध मार्ग है जिसके माध्यम से देर से औद्योगीकृत अर्थव्यवस्थाओं ने स्थायी बाहरी मजबूती हासिल की है।

सामरिक अपरिहार्यता का मार्ग: वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के माध्यम से

16.72 विनिर्माण निर्यात क्षमता रातों-रात उत्पन्न नहीं होती। इसकी नींव पैमाना, विश्वसनीयता और एकीकरण पर टिकी होती है, जो समय के साथ अनुशासित क्षमता निर्माण के माध्यम से विकसित होती है। एकीकरण का अर्थ है भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल करना तथा वैश्विक उत्पादन प्रणालियों को भारत के भीतर स्थापित करना।

16.73 वैश्विक व्यापार तेजी से अपेक्षाकृत छोटे समूह की बहुराष्ट्रीय उत्पादन नेटवर्कों के इर्द-गिर्द केंद्रित होता जा रहा है। यह भारत में ऐसी कंपनियों को आकर्षित करने के महत्व को और मजबूत करता है—सिर्फ पूँजी के स्रोत के रूप में नहीं, बल्कि निर्यात क्षमता और मुद्रा की मजबूती के आधार स्तंभ के रूप में।

16.74 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) एक समान श्रेणी नहीं है। निवेशकों की पहचान निवेश की मात्रा जितनी ही महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, परिधान, ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता वस्तुओं में कुछ वैश्विक ब्रांड विश्व व्यापार का असमान रूप से बड़ा हिस्सा नियंत्रित करते हैं।

16.75 वैश्विक व्यापार आँकड़ों से प्रमाण मिलता है कि विकसित दुनिया के चीन से होने वाले आयात का लगभग आधा हिस्सा लगभग पचास बहुराष्ट्रीय ब्रांडों की आपूर्ति श्रृंखलाओं से आता है। ये कंपनियाँ केवल उत्पादों को असेंबल नहीं करतीं। वे आपूर्तिकर्ता नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म, गुणवत्ता प्रणालियाँ और सतत डिजाइन फीडबैक लूप्स से युक्त पारिस्थितिक तंत्र का संचालन करती हैं, जो संपूर्ण उद्योगों को आकार देते हैं।

16.76 भारत के लिए, ऐसी कंपनियों को आकर्षित करना प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। यह पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण को तेज करने का साधन है। जब कोई वैश्विक ब्रांड बड़े पैमाने पर प्रतिबद्ध होता है, तो आपूर्तिकर्ता उसका अनुसरण करते हैं, कौशल गहराते हैं, मानक ऊँचे होते हैं और निर्यात नीति-प्रेरित होने के बजाय स्वाभाविक बन जाते हैं। यह स्वदेशी को क्षमता-निर्माण से सामरिक अपरिहार्यता तक ले जाने का सबसे तेज मार्ग है।

राज्य की भूमिका

16.77 इस दृष्टि में राज्य की भूमिका अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। उसे अनुशासन लागू करने में दृढ़, नियमों को अनुकूलित करने में लचीला और समर्थन आवंटित करने में निष्पक्ष होना चाहिए। दृढ़ता यह सुनिश्चित करती है कि संरक्षण अधिकार में न बदल जाए। लचीलापन नीति को धारणाओं के बजाय प्रतिक्रिया के आधार पर ढालने की अनुमति देता है। निष्पक्षता वैधता बनाए रखती है और किसी के कब्जे (कैप्चर) को रोकती है। इन गुणों का संतुलन बनाए रखना कठिन है, लेकिन वैकल्पिक नहीं। जो राज्य किसी एक आयाम में असफल रहते हैं, वे या तो पहल को दबा देते हैं, अक्षमता को जड़ बना देते हैं या प्रतिशोध (बैकलैश) को आमंत्रित करते हैं।

16.78 भारत की विविधता और संघीय संरचना को अक्सर उसके विकास पर बाधा के रूप में उद्धृत किया जाता है। वास्तव में, वे शक्ति के स्रोत हो सकते हैं। विभिन्न राज्यों के पास अलग-अलग संसाधन हैं—भौगोलिक, जनसांख्यिकीय और संस्थागत—और वे उसी अनुसार विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। एक राष्ट्रीय स्वदेशी रणनीति को राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को सक्षम करना चाहिए, परिणामों को पुरस्कृत करना चाहिए और सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रसार करना चाहिए। सरकार का कार्य दिशा निर्धारित करना, अवरोधों को दूर करना और विश्वसनीयता प्रदान करना है।

16.79 लचीलेपन से अपरिहार्यता तक की यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन आवश्यक नहीं कि हो। इसके लिए धैर्य, अनुशासन और संस्थागत साहस की आवश्यकता होती है। लेकिन यह न तो अभूतपूर्व है और न ही अप्राप्य। भारत के पास इसे आजमाने के लिए पैमाना, प्रतिभा और लोकतांत्रिक वैधता मौजूद है। जो शेष है वह है इरादे और क्रियान्वयन, नीति और संस्थाओं, अल्पकालिक दबाव और दीर्घकालिक लक्ष्यों के बीच सामंजस्य। यदि यह सामंजस्य स्थापित हो जाता है, तो आत्मनिर्भर भारत को एक खंडित दुनिया में आत्मविश्वासपूर्ण समेकन के सिद्धांत के रूप में याद किया जाएगा। सही सामंजस्य प्राप्त करने के लिए हमें राज्य की परिकल्पना को फिर से सोचना होगा। यही हम अध्याय के भाग ৷৷ में आगे करेंगे।

***